

विविध नागरिक

राजेंद्र नाथ मित्तल और के.एस. तिवाना, जे.जे के समक्ष

मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ, आदि,-प्रतिवादी।

1975 की सिविल रिट संख्या 4709

14 जुलाई 1976

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 12 और 226-आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम (1947 का XVIII)-धारा 3-आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश 1955-खंड 2 (एएएए) 3 (i) 5 (3) (ii) परंतुक, 8 और 8-ए-आयात व्यापार नियंत्रण नियम और प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका-पैराग्राफ 97 (3) (सी)-वस्तुओं की बिक्री अधिनियम (1930 का IX)-धारा 39-भारतीय राज्य व्यापार निगम, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी -क्या कोई "प्राधिकरण" और रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है-संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न होने वाले विवाद-पीड़ित पक्ष-क्या अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया जा सकता है-निगम के नाम पर नहर माल के लिए आयात लाइसेंस-क्या रिलीज ऑर्डर धारकों का एजेंट-C.I.F। अनुबंध-संपत्ति में-जब गुजरती है।

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 12 और 226-आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम (1947 का XVIII)-धारा 3-आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश 1955-खंड 2 (एएएए) 3 (i) 5 (3) (ii) परंतुक, 8 और 8-ए-आयात व्यापार नियंत्रण नियम और प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका-पैराग्राफ 97 (3) (सी)-वस्तुओं की बिक्री अधिनियम (1930 का IX)-धारा 39-भारतीय राज्य व्यापार निगम, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी -क्या कोई "प्राधिकरण" और अधिकार क्षेत्र को लिखने के लिए उत्तरदायी है-संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न होने वाले विवाद-पीड़ित पक्ष-क्या अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया जा सकता है-निगम के नाम पर नहर माल के लिए आयात लाइसेंस-क्या रिलीज ऑर्डर धारकों का एजेंट-सी.आई.एफ अनुबंध-संपत्ति-कब पारित होता है।

माना गया कि "प्राधिकरण" शब्द को भारत के संविधान 1950 में परिभाषित नहीं किया गया है। किसी निगमित निकाय के विरुद्ध रिट जारी किए जाने से पहले, तीन बातों को साबित करने की आवश्यकता होती है: (i) कि यह एक वैधानिक निकाय है और इसका निर्माण एक कानून के लिए होता है जिसमें इससे उत्पन्न होने वाली शक्तियों और दायित्वों के साथ और इसके कार्य कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं; (ii) कि यह सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है और (iii) कि एक वैधानिक नियम का उल्लंघन किया गया है। जो निगम कानूनों द्वारा बनाए गए हैं और वैधानिक कार्यों को पूरा करते हैं, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। राज्य व्यापार निगम एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह कंपनी अधिनियम और न ही आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का निर्माण नहीं है। यह कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है, इसका अपना ज्ञापन और संघ के लेख हैं, यह निदेशक मंडल द्वारा शासित है और अपना व्यवसाय कर रहा है। इसके चारों ओर एक कॉर्पोरेट घूंघट है जिसे छेदा नहीं जा सकता है। यह न तो एक वैधानिक निकाय है और न ही इसके कार्य सरकारी

या सार्वजनिक हैं। यह गुप्त सौदों पर नियंत्रण रखता है ताकि इनके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का कोई नुकसान न हो। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में निहित प्राधिकरण के रंग और जाल का अभाव है और इसके परिणामस्वरूप इसके खिलाफ एक रिट नहीं है।

(पैरा 26 और 27)

अभिनिर्धारित किया गया कि संविदात्मक दायित्वों का कोई भी उल्लंघन पीड़ित पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के विवेकाधीन न्यायशास्त्र को लागू करने का अधिकार नहीं देता है।

(पैरा 32)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1955 में अंतर्विष्ट नियम दो प्रकार के अनुज्ञप्ति पर विचार करते हैं; एक उन वस्तुओं के लिए है जो कैनालाइज्ड नहीं हैं और दूसरा कैनालाइज्ड वस्तुओं के लिए है। पहले वाले के मामले में आयात लाइसेंस सीधे आवेदकों के नाम पर जारी किए जाते हैं और बाद वाले के मामले में, आयात व्यापार नियंत्रण नियम और प्रक्रिया के पैराग्राफ 97 (3) (सी) में निहित आयात नीति के कारण, इसे नहर बनाने वाली एजेंसी के नाम पर जारी किया जाता है। आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के नियम 5 (3) (ii) के प्रावधान में राज्य व्यापार निगम को 1955 के नियमों के नियम 5 (3) (ii) के कार्यान्वयन से बाहर रखा गया है। इसी तरह आदेश के नियम 8 और 8-ए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से शब्द को सम्मिलित करके एक लाइसेंसधारी और राज्य व्यापार निगम के बीच अंतर करते हैं। राज्य व्यापार निगम शब्द के सामान्य अर्थ में एक लाइसेंसधारी के रूप में समझने के लिए नहीं है और यह इस कारण से है कि यह इंडेंट आदि में प्रतिनिधित्व करता है कि यह रिलीज ऑर्डर धारकों की ओर से कार्य करता है। नियमों के परिशिष्ट 34 में निहित प्रो फॉर्मा में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में लाइसेंसधारी रिलीज ऑर्डर धारक हैं और राज्य व्यापार निगम को यह नाम केवल आयात व्यापार नियंत्रण आदेश के कानून की कल्पना के कारण दिया गया है। इसलिए, राज्य व्यापार निगम उन वस्तुओं का मालिक नहीं है जिनका वह आयात करता है। राज्य व्यापार निगम रिलीज ऑर्डर धारकों के एजेंट के रूप में कार्य करता है।

(पैरा 46 और 47)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. आई. एफ. अनुबंधों के मामले में, जब भी प्रथागत दस्तावेज, अर्थात् लेडिंग बिल, आदि तैयार किए जाते हैं और खरीदारों को वितरित किए जाते हैं, तो माल में निहित संपत्ति उन्हें हस्तांतरित कर दी जाती है।

(पैरा 54)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, मेंडमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश का एक रिट जारी किया जाए: —

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना;

(ii) प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को आयातित सामग्री देने का निर्देश दिया जाए;

(iii) यह अभिनिर्धारित किया जाए कि याचिकाकर्ता किसी तरह के विलम्ब आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, और वह आयातित माल के कब्जे का हकदार है;

(iv) याचिकाकर्ता को 'पी-1' से 'पी-37' के अनुलग्नक के मूल दाखिल करने से छूट दी जाएगी;

(v) यह अभिनिर्धारित किया जाए कि याचिकाकर्ता आयातित माल के कब्जे का भी हकदार है-इंडेंट नंबर 7015/72 या वैकल्पिक रूप से वह इस ओर से याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए धन की वापसी का हकदार है।

(vi) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और उपयुक्त समझे और उन सभी परिणामी राहतों को प्रदान कर सकता है जिनके लिए याचिकाकर्ता को हकदार पाया जा सकता है;

(vii) इस याचिका का खर्च भी याचिकाकर्ता को दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के लिए वकील जे.एल. गुप्ता और वकील जी.सी. गुप्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के लिए वकील, कुलदीप सिंह।

आर. सी. डोगरा, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के लिए।

प्रतिवादी नंबर 6 के लिए जवाला प्रसाद चोपड़ा, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट (आर. एम. सूरी, उनके साथ वकील)।

गुरबचन सिंह, प्रतिवादी संख्या 7 के वकील।

निर्णय

कुलवंत सिंह तिवाना, न्यायमूर्ति

(1) यह निर्णय सिविल रिट याचिका सं. 1975 का 4709, मेसर्स लांबा द्वारा दायर, उद्योग और सिविल रिट याचिका सं। मेसर्स हरबंस एंड कंपनी द्वारा भारत सरकार के सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ के खिलाफ दायर 1975 का 238, प्रत्यर्थी नं। 1, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रतिवादी नं. 2, और अन्य, क्योंकि कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न इनमें शामिल हैं।

(2) मेसर्स लांबा, इंडस्ट्रीज, लुधियाना, जो एक भागीदार कंपनी है और कपड़ा और होजरी के सामान के निर्माण में लगी हुई है, ने सिविल रिट याचिका नं। भारत संघ के विरुद्ध 1975 का 4709, प्रत्यर्थी सं. 1, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, प्रत्यर्थी नं. 2 और अन्य यह कहते हुए कि-आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के द्वारा (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रतिबंधित और प्रतिबंधित या अन्यथा नियंत्रित करने का प्रावधान किया है। वर्ष 1960 में, भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए "निर्यात संवर्धन योजना" के रूप में जानी जाने वाली एक योजना शुरू की। गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण और निर्यात। इस योजना के अनुसार एक व्यक्ति, जो विदेश में माल का निर्यात करता है, उसे समान मूल्य के माल के देश में आयात की अनुमति दी जानी थी। याचिकाकर्ता-फर्म ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। वर्ष 1956 में, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद S.T.C. के रूप में जाना जाता है। इसे आम तौर पर राज्य व्यापारिक देशों के साथ व्यापार के आयोजन और उपक्रम के उद्देश्य से और निर्यात आदि को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रपति और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के सचिवों के साथ इसके शेयरधारकों के रूप में पंजीकृत किया गया था। वर्ष 1967 में, भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के आयात को सीमित करने का निर्णय लिया। यह अधिसूचित किया गया था-सार्वजनिक सूचना सं। 172-आई. टी. सी. (पी. एन.)/67, दिनांक 25 नवंबर, 1967, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत

सरकार ने "ऊन कच्चे, ऊन के शीर्ष आदि के सभी आयातों को सीमित करने" का निर्णय लिया है, जैसा कि क्रम संख्या में दिया गया है। वर्ष 1967 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति अनुसूची 1 के भाग 5 में 47. यह नीति उपर्युक्त आदेश जारी होने के तुरंत बाद लागू की गई थी। इस निर्णय के बाद यह निर्णय लिया गया कि संबंधित निर्यातक F.O.B के 60 प्रतिशत की सीमा तक वस्तुओं का आयात करने के हकदार होंगे। निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य। 60 प्रतिशत की आयात पात्रता में से याचिकाकर्ता-फर्म संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकरण के पत्र के आधार पर सीधे 30 प्रतिशत और शेष 30 प्रतिशत S.T.C. के माध्यम से आयात करने का हकदार था। वर्ष 1969 से 1971 में याचिकाकर्ता ने लगभग 5 से 6 लाख मूल्य के सामानों का निर्यात किया और इस प्रकार 5 करोड़ रुपये की आयात पात्रता अर्जित की। 3 लाख। इसमें से एक लाख रुपये मूल्य का सामान बरामद किया गया। 20, 299 को S.T.C के माध्यम से आयात किया जाना था। प्रक्रिया निर्धारित और अनुसरण किया गया था कि याचिकाकर्ता को S.T.C द्वारा रेलवे रसीदें दी गई थीं। और बैंक में धन जमा होने पर माल याचिकाकर्ता-फर्म को जारी कर दिया गया। जहां तक आयातित वस्तुओं की निकासी आदि का संबंध था, प्रक्रिया का पालन S.T.C द्वारा किया जाना था। जब भी याचिकाकर्ता द्वारा पैसे का भुगतान किया जाता था तो उसे सामान जारी कर दिया जाता था। जनवरी, 1972 में, याचिकाकर्ता-फर्म के एक प्रतिनिधि को विभिन्न रिलीज आदेशों के आधार पर आयात के लिए उपलब्ध नमूनों में से सामग्री का चयन करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। सामग्री का चयन याचिकाकर्ता-फर्म के प्रतिनिधि द्वारा किया गया था और आदेश S.T.C द्वारा आयात के लिए रखा गया था। विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं के मान्यता प्राप्त स्थानीय एजेंटों के साथ। इंडेंट नं. 7014/72, दिनांक 15 फरवरी, 1972 रुपये मूल्य के सामान की खरीद के लिए रखा गया था। इस इंडेंट की 20,299 प्रति याचिका के अनुलग्नक पी-2 में है। यह आदेश ऊनी कपड़ों के आयात के लिए था। यह इंडेंट याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा 15 फरवरी, 1972 को एक पत्र के साथ प्राप्त किया गया था, जिसकी प्रति S.T से याचिका के लिए अनुलग्नक P-3 है। सी. बाद में प्राप्त विभिन्न दस्तावेजों के बीच याचिकाकर्ता-फर्म को विदेशी आपूर्तिकर्ता से पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति याचिका के लिए अनुलग्नक पी-4 है, एक प्रमाण पत्र के साथ कि "सामान विधिवत काटा गया है, विकृत किया गया है जिसका उपयोग पहनने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है"। एस. टी. सी. ने मेसर्स कैमल निटिंग एंड टेक्सटाइल मिल्स, लुधियाना, प्रतिवादी नं. 7,-इंडेंट नं. 7015/72. भारत में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के एजेंट मेसर्स मोहन लाई एंड संस ने याचिकाकर्ता-फर्म को सूचित किया कि एक निरीक्षण के माध्यम से सिद्धांतों ने इंडेंट नंबर 7014 और 7015 के मुकाबले संयुक्त रूप से 66 गांठें भेज दी हैं। इस पत्र की प्रति याचिका के अनुलग्नक पी-5 में दी गई है। याचिकाकर्ता-फर्म को 66 गांठों के लिए संयुक्त रूप से भुगतान करने और उनकी मंजूरी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। इसी तरह की सेवा याचिकाकर्ता फर्म को अपने बैंकरों के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-6 है। हालाँकि, याचिकाकर्ता-फर्म ने प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की। एस. टी. सी. द्वारा टेलीफोन पर याचिकाकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह इस शर्त पर दस्तावेजों का सम्मान करे कि जवाब नं. 7, पैसे के अपने हिस्से का भुगतान करेगा। 16 अगस्त, 1972 को याचिकाकर्ता-फर्म को एसटीसी से इसी आशय का पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-7 है। एसटीसी द्वारा दिए गए जवाब पर याचिकाकर्ता-फर्म ने उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान के लिए 38,957.40 रुपये का भुगतान किया और प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से भी। लेकिन, याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा की गई मांगों और आग्रह के बावजूद न तो प्रतिवादी संख्या 7 ने भुगतान किया और न ही माल की निकासी की दिशा में कोई प्रयास किया। याचिकाकर्ता-फर्म ने S.T.C पर जोर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से उसके द्वारा भुगतान की गई राशि प्राप्त करना। उस ओर से याचिकाकर्ता-फर्म और एस. टी. सी. के बीच काफी पत्राचार हुआ।

(3) इस बीच सीमा शुल्क के कलेक्टर, बॉम्बे रेस्पॉन्डेंट नंबर 5 ने याचिकाकर्ता-फर्म को सूचित किया- जिसकी पत्र प्रति याचिका के लिए अनुलग्नक पी-13 है, कि जांच पर यह पाया गया कि सामान ऊनी

चिथड़े नहीं थे, बल्कि उपयोगी ऊनी परिधान थे। इस नोटिस की प्राप्ति पर याचिकाकर्ता-फर्म ने सीमा शुल्क कलेक्टर को एक जवाब भेजा और माल को विकृत करने की पेशकश की और इस उद्देश्य के लिए मेसर्स ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, लुधियाना को नामित किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने याचिकाकर्ता-फर्म को सूचित किया कि मेसर्स ओसवाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, लुधियाना के पास जगह की कमी के कारण, उन्होंने किसी अन्य कंपनी के सामान को विकृत नहीं किया था और किसी अन्य विद्रोह के नामांकन के लिए जोर दिया था। याचिकाकर्ता-फर्म ने तब विपणन प्रबंधक, भारतीय राज्य व्यापार निगम, लिमिटेड, प्रतिवादी नं. 4, लुधियाना में और प्रत्यर्थी संख्या 7 के लिए भुगतान किए गए धन का भुगतान करने के लिए उन्हें प्रभावित किया। एसटीसी ने याचिकाकर्ता-फर्म को भुगतान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 7 को पत्र भी लिखे थे। याचिकाकर्ता-फर्म के प्रतिनिधि को एसटीसी द्वारा अपने निदेशक से मिलने के लिए कहा गया था और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता-फर्म के प्रतिनिधि ने निदेशक से मुलाकात की, जिन्होंने श्री एम. एम. गुप्ता को मामले को देखने और एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। लेकिन मामला तय नहीं हो सका। 5 सितंबर, 1974 को, याचिकाकर्ता-फर्म को डॉक्स मैनेजर, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, प्रतिवादी संख्या 6 से एक सूचना मिली, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-23 है, कि चूंकि माल को मंजूरी नहीं दी गई है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटाया जा रहा है। याचिकाकर्ता-फर्म ने इस कार्रवाई के खिलाफ तुरंत पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणों को प्रस्तुत किया। आपत्ति संख्या 6 ने याचिकाकर्ता-फर्म को डिमारेज का भुगतान करने के लिए कहा, जो प्रतिवादी संख्या 6 के अनुसार, 1,70,000 रुपये की राशि के लिए जमा हुआ। याचिकाकर्ता-फर्म, तब से, मामले को निपटाने के लिए अधिकारियों को लगातार लिख रही है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। 24 फरवरी, 1975 को याचिकाकर्ता-फर्म के प्रतिनिधि ने एसटीसी के निदेशक श्री एम. एन. मिश्रा से मुलाकात की और पैसे वापस करने का अनुरोध किया। श्री एम. एन. मिश्रा ने याचिकाकर्ता-फर्म के निवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से उसके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के समायोजन का आदेश दिया। श्री एम. एन. मिश्रा से मिलने के बाद, याचिकाकर्ता-फर्म ने आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति मुख्य विपणन प्रबंधक, एसटीसी, प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुलग्नक पी-27 है। याचिकाकर्ता-फर्म ने श्री एम. एन. मिश्रा के आदेश के कार्यान्वयन के लिए फिर से प्रतिनिधित्व किया। याचिकाकर्ता-फर्म ने प्रतिवादी नं. 6 विमुद्रीकरण की छूट के लिए, जिसकी प्रति अनुलग्नक 24 है। याचिकाकर्ता-फर्म आयातित माल की रिहाई के लिए प्रतिवादी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व कर रही थी, -इंडेंट नंबर 7014/72 और प्रतिवादी नंबर 7 की ओर से आयातित माल के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के समायोजन के लिए।

(4) याचिकाकर्ता-फर्म का दावा है कि एस.टी.सी. यूनिका ऑफ इंडिया का एजेंट है, प्रतिवादी संख्या 1 और उसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अर्जित आयात पात्रता के विरुद्ध विभिन्न वस्तुओं का आयात करना है। राशि लगभग रु. याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किया गया 43,000 रुपये अवरुद्ध पड़ा हुआ है और वह सामान की डिलीवरी का हकदार है और एसटीसी प्रतिवादी संख्या 2 की सामान वितरित न करने की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना थी। एसटीसी, प्रतिवादी नंबर 2, माल आयात करने का उपक्रम करने वाला और याचिकाकर्ता-फर्म ने उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर अच्छे विश्वास के साथ पैसे का भुगतान किया है, वह माल की डिलीवरी का हकदार है और प्रॉमिसरी एस्टॉपेल / न्यायसंगत एस्टॉपेल के नियम के तहत आकर्षित होता है। मामले की परिस्थितियाँ, एस.टी.सी. द्वारा माल की डिलीवरी न होना। इसके परिणामस्वरूप न्याय का दुरुपयोग हुआ है। याचिकाकर्ता-फर्म को रुपये की विलंब शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए कहने में प्रतिवादी संख्या 6 की कार्रवाई। 3 लाख बिल्कुल अवैध है। माल एसटीसी द्वारा आयात किया गया था, जिसका विवरण याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा दिया गया था। याचिकाकर्ता फर्म सामान के विवरण में पाई गई किसी भी कमजोरी के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और किसी भी अधिक भुगतान के लिए कहे बिना उस सामान को अपने कब्जे में लेने का हकदार है। याचिकाकर्ता-फर्म को इस तथ्य के बावजूद अधिकारियों द्वारा माल वितरित करने में विफलता के कारण भारी और आवर्ती

नुकसान हुआ है कि उसने पूरा पैसा चुका दिया है और उसने इस विश्वास पर माल निर्यात किया था कि यह कच्चा हो जाएगा। निर्यातित माल के विरुद्ध सामग्री। चूंकि याचिकाकर्ता-फर्म ने एस.टी.सी. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 7 के पैसे का हिस्सा चुका दिया है। यह इसलिए, वह उस धनराशि को वापस भुगतान करने या अन्य आयातों के विरुद्ध समायोजित करने के लिए उत्तरदायी है।

(5) उपर्युक्त तथ्यों पर याचिकाकर्ता-फर्म ने उत्तरदाताओं के खिलाफ याचिकाकर्ता-फर्म को आयातित सामग्री वितरित करने के निर्देश के लिए सर्टिओरीरी, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रार्थना की है और एक घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता-फर्म किसी विलंब शुल्क आदि का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी, और वह कब्जे की हकदार है। आयातित माल का और याचिकाकर्ता-फर्म को भी आयातित माल के कब्जे का हकदार घोषित किया जाए, इंडेंट संख्या 7015 के माध्यम से या उस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए धन की वापसी का हकदार होने के विकल्प में।

(6) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, प्रतिवादी संख्या, और उसके विपणन प्रबंधक, प्रतिवादी संख्या 4, ने अपने रिटर्न में प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं कि रिट याचिका एस.टी.सी. के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं थी। जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है; यह याचिका प्रतिवादियों में से एक के रूप में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के गैर-जेंडर के लिए खराब थी क्योंकि माल की आपूर्ति याचिकाकर्ता-फर्म को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की जानी थी; विवाद का मामला पूरी तरह से अनुबंध से उत्पन्न एक नागरिक प्रकृति का था और सिविल रिट याचिका अनुबंध संबंधी दायित्व को लागू करने का कोई उपाय नहीं है; कि याचिकाकर्ता ने गलतबयानी की है। याचिका में कुछ छुपाया गया है और इस आधार पर इसे खारिज किया जा सकता है: कि रिट याचिका में तथ्य के कई विवादित प्रश्न हैं जो इस न्यायालय में वर्तमान कार्यवाही में सुविधाजनक रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं; कि रिट याचिकाकर्ता-फर्म के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसे इस रिट याचिका के माध्यम से लागू किया जा सके।

(7) गुणागुण के आधार पर, आयातित वस्तुओं को प्रतिबंधित, प्रतिबंधित और नियंत्रित करने की भारत सरकार की नीति और आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित आदेश, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-1 है, को स्वीकार किया गया था। इस मामले में अनुबंध में सामान पुराने ऊनी कपड़े बताए गए थे। रेलवे रसीद के माध्यम से माल की डिलीवरी के बारे में रिट याचिका के पैरा 7 में याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा इंगित प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि उत्तरदाताओं ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त शिपिंग दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से माल का हस्तांतरण किया था। इस मामले में प्रेषण दस्तावेजों को याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा अपने बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। दस्तावेजों के हस्तांतरण और आयातित माल की सफाई और हैंडलिंग की व्यवस्था संबंधित आयातकों, यानी याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा की जानी थी। उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता-फर्म के प्रतिनिधि को सामग्री का चयन करने के लिए दिल्ली बुलाने से इनकार कर दिया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता-फर्म को चयन के लिए ऊनी कपड़ों के नमूने उपलब्ध नहीं कराए थे। रिलीज ऑर्डर-धारक दिल्ली में उत्तरदाताओं के कार्यालय में आयोजित आवधिक खरीद बैठकों में भाग लेते हैं और विभिन्न विदेशी-आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सामग्री का चयन करते हैं। उन बैठकों में कोई नमूना नहीं दिखाया जाता है। अनुबंध, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक पी 2 है, को याचिकाकर्ता-फर्म की ओर से उत्तरदाता-प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था जैसा कि उसके पत्र में कहा गया है, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-3 है। इंडेंट नंबर, 7014 और 2015 के लिए शिपिंग दस्तावेज याचिकाकर्ता-फर्म के नाम पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गलती से तैयार किए गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि एस.टी.सी. ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में अपना क्रेडिट पत्र

स्थापित किया है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक आर. 2/2 है, जो विशेष रूप से वहां संलग्न है- एक बयान के साथ यह दर्शाता है कि शिपिंग दस्तावेज़ अंतिम उपयोगकर्ताओं के कारण एसटीसी के नाम पर बनाए जा सकते हैं। बयान में उल्लेख किया गया है। यह विदेशियों के विशेष अनुरोध पर था। आपूर्तिकर्ताओं ने अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से कहा कि इस प्रतिवादी ने इन दस्तावेजों को सेवानिवृत्त कर दिया और याचिकाकर्ता-फर्म के बैंकों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने वास्तव में अक्टूबर, 1972 में भुगतान किया था, जटिलताओं से बचने के लिए उत्तर देने वाले-प्रतिवादियों ने अलग-अलग चालान तैयार किए, जिसमें अलग-अलग देय राशि का संकेत दिया गया था। याचिकाकर्ता-फर्म और प्रतिवादी नंबर 7. याचिकाकर्ता-फर्म ने बिना किसी दबाव के इन दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया और स्वेच्छा से प्रतिवादी नंबर 7 से शेयर राशि वसूलने की पेशकश की। इसके बावजूद एस.टी.सी. याचिकाकर्ता-फर्म को अपनी हिस्सेदारी की राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी नंबर 7 से अनुरोध किया और याद दिलाया। इस संबंध में किसी भी टेलीफोनी निर्देश या बातचीत से इनकार कर दिया गया। एसटीसी ने प्रतिवादी नंबर 7 से भुगतान की गई राशि प्राप्त करने का प्रयास किया। यह एक सी.आई.एफ. था, खरीद जिसके तहत जब माल गहरे समुद्र में होता है तो दस्तावेज़ का स्थानांतरण स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त सबूत होता है और याचिकाकर्ता- दस्तावेजों को स्वीकार करने वाली फर्म खेप की निकासी के लिए जिम्मेदार थी। इस बात से इनकार किया गया कि यह एसटीसी द्वारा आयात था। लेकिन एक विशिष्ट मांगपत्र और एस.टी.सी. के दायित्व के आधार पर याचिकाकर्ता-फर्म के अनुरोध पर था। माल की निकासी से भी इनकार कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा भुगतान की गई राशि के समायोजन के लिए श्री एमएन मिश्रा को दिए गए किसी भी प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता-फर्म का प्रतिनिधि उक्त निदेशक से मिल रहा था।, पेटी के रवैये के बावजूद। टीनर-फर्म एस.टी.सी. उसे चिकने ऊन की नई खरीद की अनुमति दी गई जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। श्री एम. एन. मिश्रा ने किसी भी समायोजन या किसी भी आश्वासन की अनुमति देने के आरोप से इनकार करते हुए एक हलफनामा दायर किया।

(8) पोर्ट ट्रस्ट, बॉम्बे, प्रतिवादी संख्या 6 ने, रिटर्न में, याचिका की सुनवाई के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई क्योंकि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर इसके खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ। गुण-दोष के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि एसएस द्वारा 66 गांठों के स्थान पर केवल 60 गांठें वितरित की गईं। बंबई के बंदरगाह पर आंध्र राज्य। चूंकि याचिकाकर्ता-फर्म के क्लियरिंग एजेंट ने डॉकयार्ड से गांठें नहीं हटाई थीं, इसलिए उसे नीलामी के लिए नोटिस जारी किया गया था, दिनांक 12 जून, 1974 के पत्र के माध्यम से, जिसकी प्रति प्रतिवादी संख्या 6 के लिखित बयान के लिए अनुलग्नक 'ए' है। याचिकाकर्ता-फर्म को पत्र, दिनांक 23 सितंबर, 1974, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक 'डी' है, के माध्यम से पोर्ट ट्रस्ट शुल्क का भुगतान करने और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विलंब शुल्क की छूट के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया था: -

"1. आयातक की ओर से औपचारिक आवेदन। याचिकाकर्ता की ओर से छूट के लिए आवेदन करने के लिए क्लियरिंग एजेंटों को अधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र।

2. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट रसीद मूल रूप में।

3. सीमा शुल्क जांच चालान और विनिर्देश,

4. यदि सामान किसी भी स्तर पर अप्राप्य हो तो लॉग प्रविष्टि करें।

5. वैगनों के देर से प्लेसमेंट के मामले में रेलवे प्रबंधक का प्रमाण पत्र।"

हालाँकि, याचिकाकर्ता ये दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहा। प्रतिवादी नंबर 6 ने फिर से याचिकाकर्ता-फर्म से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पारित प्रवेश बिल, सीमा शुल्क जांच किए गए चालान प्रस्तुत करने के लिए कहा। सीमा शुल्क द्वारा जारी सकल वजन और जब्ती आदेश दिखाते हुए, इस पत्राचार पर याचिकाकर्ता-फर्म की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रस्तुत किया कि रुपये का भुगतान करने पर माल की निकासी पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। 18 अगस्त, 1975 तक विलंब शुल्क के रूप में 2,49,716.65 रु. का भुगतान किया गया।

(9) प्रत्यर्थी नं. 7 ने आदेश देने और 1972 के इंडेंट नं. 7015 के माल के लिए याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा धन के भुगतान को भी स्वीकार किया। हालाँकि, इसने जोर देकर कहा कि यदि याचिकाकर्ता-फर्म (प्रतिवादी संख्या 7) को डिमरेज आदि के किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना सामान दिया जाता है, तो प्रतिवादी-फर्म राशि का भुगतान करने को तैयार है। प्रत्यर्थी-फर्म ने याचिकाकर्ता-फर्म और उसके साथ एसटीसी के पत्राचार को स्वीकार किया और कहा कि प्रतिवादी-फर्म ने कभी भी भुगतान करने से इनकार नहीं किया था और अभी भी ऐसा करने के लिए तैयार था बशर्ते सामान उसे दिया जाए।

(10); मेसर्स हरबंस एंड कंपनी द्वारा दायर 1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 238 के तथ्य भारत सरकार द्वारा योजना शुरू करने, आयात पर प्रतिबंध लगाने और जारी करने के बारे में मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज द्वारा दायर सिविल रिट याचिका के साथ समान हैं। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कच्चे ऊन, ऊन टॉप आदि के आयात को रद्द करने का आदेश दिया गया। माल के हस्तांतरण को लेकर याचिकाकर्ता-फर्म का मामला मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज फर्म के साथ भी आम है। माल के आयात के संबंध में, एफओबी के 60 प्रतिशत की सीमा तक। निर्यात किए गए माल का मूल्य, मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज के मामले में उसी सिद्धांत पर, इस याचिकाकर्ता-फर्म ने रुपये की आयात पात्रता अर्जित करने का दावा किया है। वर्ष 1970 में 32,806 जिसके लिए अलग-अलग रिलीज़ ऑर्डर जारी किए गए थे कृपादृष्टि। याचिकाकर्ता-फर्म का दावा है कि आयात के लिए उपलब्ध नमूनों में से सामग्री का चयन करने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा 15 जनवरी, 1972 को टेलीग्राफिक रूप से बुलाया गया था। याचिकाकर्ता-फर्म के प्रतिनिधि ने सामग्री का चयन किया और एस.टी.सी. द्वारा इसके आयात का आदेश दिया। आपूर्तिकर्ता के विदेश में मान्यता प्राप्त एजेंट के साथ। पहला ऑर्डर 16 फरवरी, 1972 को इंडेंट संख्या 618 के तहत रुपये के सामान के लिए दिया गया था। 16,403 और दूसरा आदेश, - मांगपत्र संख्या 625 दिनांक 17 फरवरी, 1972 द्वारा, रुपये की राशि के लिए रखा गया था। 16,240. ये आदेश ऊनी कपड़ों के आयात से संबंधित हैं। मांगपत्र की प्रतियां इस याचिका के अनुलग्नक पी-2 और पी-3 हैं। 23 मई 1972 को एस.टी.सी. इंडेंट नंबर 618 से संबंधित दस्तावेज भेजे और याचिकाकर्ता-फर्म को 7 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा। याचिकाकर्ता-फर्म ने अपेक्षित राशि और विभिन्न शुल्क जमा किए और फिर माल को लुधियाना तक आगे भेजने के लिए सीमा शुल्क से मंजूरी पाने के लिए बॉम्बे में अपने समाशोधन एजेंटों को दस्तावेज भेजे। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता-फर्म ने सभी औपचारिकताओं का पालन किया, सामान उसे प्राप्त नहीं हुआ। एस.टी.सी. 30 जनवरी, 1973 को सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, बॉम्बे द्वारा जारी नोटिस की एक प्रति भेजी गई, जो इस याचिका के लिए अनुलग्नक पी -5 है, इस आशय के साथ कि खेप में पूरी तरह से सेवा योग्य ऊनी वस्त्र शामिल थे जो शुल्क योग्य वस्तु थी और वैध परमिट के अलावा इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने यह स्थिति अपनाई कि सामान जब्त किया जा सकता है। कुछ समय बाद याचिकाकर्ता-फर्म को इंडेंट नंबर 625 के माध्यम से आयातित माल के दस्तावेज भी प्राप्त हुए। चूंकि याचिकाकर्ता-फर्म को 1972 के इंडेंट नंबर 618 के खिलाफ माल के बारे में अच्छा अनुभव नहीं था, जिसके

बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा था। जारी किया गया, यह (याचिकाकर्ता-फर्म), - दिनांक 2 जनवरी, 1973 को पत्र के माध्यम से एस.टी.सी. से अनुरोध किया गया। इंडेंट नंबर 625 के संबंध में पैसा जमा करने से पहले माल को मंजूरी दिलाने के लिए। इस पत्र की प्रति इस याचिका के लिए अनुलग्नक पी-7 है। एस.टी.सी. द्वारा इस पत्र का उत्तर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता-फर्म ने सीमा शुल्क अधिकारियों को एक जवाब भेजा, जिसकी प्रति इस याचिका के अनुबंध पी-8 में है, कि माल एस.टी.सी. के माध्यम से आयात किया गया था। (प्रतिवादी संख्या 2) और इस प्रकार यदि सामान मांगपत्र में दिए गए विवरण के साथ मेल नहीं खाता है तो यह (याचिकाकर्ता-प्रथम) जिम्मेदार नहीं है। 8/9 मई, 1973 को याचिकाकर्ता-फर्म को एस.टी.सी. से एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ। (प्रतिवादी संख्या 2) को 12 मई 1973 से पहले माल साफ़ करना था, ऐसा न करने पर उन्हें नीलाम किया जाना था। याचिकाकर्ता-फर्म ने एक टेलीग्राफिक उत्तर भेजकर सूचित किया कि वह (याचिकाकर्ता-फर्म) भुगतान करने को तैयार है यदि एस.टी.सी. (प्रतिवादी संख्या 2) माल को खाली करने और रेलवे रसीद के साथ दस्तावेजों को अपने बैंकों को सौंपने का वचन देता है। एस.टी.सी. ने पत्र दिनांक 9 मई, 1973, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-11 है, के माध्यम से याचिकाकर्ता-फर्म को सूचित किया कि वह (एस.टी.सी.) भविष्य में लंबित मामलों में कोई सेवा प्रदान नहीं करेगी यदि माल 12 मई से पहले मंजूरी नहीं दी गई।, 1973. इसके बाद याचिकाकर्ता-फर्म और एस.टी.सी. के बीच आगे के पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया। (प्रतिवादी संख्या 2). एस. टी. सी. हालाँकि, दोहराया गया कि यदि याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा माल को मंजूरी नहीं दी गई है तो वह लंबित मांगपत्रों पर ध्यान नहीं देगी जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता-फर्म ने अपने भागीदार के माध्यम से एस.टी.सी. के अधिकारियों से मुलाकात की। 1 सितंबर, 1973 को, जिन्होंने उचित कदम उठाने का वादा किया था, लेकिन उस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता-फर्म माल का निर्यात कर रही थी और लगातार नई पात्रता अर्जित कर रही थी और जो माल वह आयात करने का हकदार था, वह वास्तव में आयात नहीं किया जा रहा था। इसलिए, याचिकाकर्ता-फर्म ने अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए आयात लाइसेंस को फिर से वैध करने और चर्चा के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति याचिका में संलग्नक पी-18 है। . अनुस्मारक के बावजूद याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से कुछ भी नहीं सुना गया। इसके द्वारा अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस दिया गया था, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-21 है। एस.टी.सी. के अधिकारियों के साथ चर्चा पर लुधियाना में, एक निर्णय आया जिसके अनुसार याचिकाकर्ता-फर्म को यह वचन देने के लिए कहा गया कि वह इंडेंट नंबर 625 के तहत आयातित माल के स्थान पर चिकना ऊन आदि स्वीकार करने को तैयार होगा और यह भी होगा ब्याज के साथ-साथ बिक्री कर, यदि कोई हो, का भुगतान करने को तैयार है। याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा अपेक्षित वचन पत्र, दिनांक 30 नवंबर, 1973 के पत्र के माध्यम से दिया गया था, जिसकी प्रति इस याचिका के अनुबंध पी-22 में है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर एस.टी.सी. और याचिकाकर्ता-फर्म के भागीदार द्वारा मुख्य विपणन प्रबंधक एस.टी.सी. के साथ व्यक्तिगत चर्चा पर। और अन्य अधिकारियों ने उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया गया। यहां तक कि मुख्य विपणन प्रबंधक ने निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष को सूचित किया कि याचिकाकर्ता फर्म का मामला उनके द्वारा देखा जा रहा है। याचिकाकर्ता-फर्म ने कहा कि भारत संघ, प्रतिवादी नंबर 1, ने एस.टी.सी. के माध्यम से आयात को रद्द कर दिया है। प्रतिबंध लगाने की शक्तियाँ केंद्र सरकार और एस.टी.सी. में निहित हैं। उसके पास कोई प्रतिबंध लगाने की कोई शक्ति नहीं है। एसटीसी की कार्रवाई भारत सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता-फर्म को माल के आयात की अनुमति देने से इनकार करना पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता-फर्म ने एसटीसी के निर्देशों के अनुसार 1972 के इंडेंट नंबर 618 के तहत आयातित माल के संबंध में उक्त राशि जमा की थी, जो पिछले दो वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध पड़ी हुई है। एस.टी.सी. याचिकाकर्ता-फर्म को माल जारी करने के लिए कुछ नहीं किया है। यदि याचिकाकर्ता-फर्म

धनराशि का कोई अन्य जमा करती है तो माल फिर से जारी नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यों के मद्देनजर याचिकाकर्ता-फर्म ने एस.टी.सी. से अनुरोध किया था। यह गारंटी देने के लिए कि आयातित माल दस्तावेजों में दिए गए विवरण से मेल खाएगा। एस.टी.सी. ऐसी गारंटी देने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में एस.टी.सी. का आग्रह मनमाना है और उसे प्रदत्त शक्तियों से अधिक है। इसकी कार्रवाई पूर्णतः न्यायसंगत होने के कारण कायम नहीं रह सकती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत याचिकाकर्ता-फर्म को व्यवसाय चलाने का मौलिक अधिकार है जो वर्तमान मामले में पूरी तरह से विफल हो गया है। यह अपने द्वारा निर्यात किये गये माल के अनुपात में माल आयात करने का हकदार है। मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत/प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि एस.टी.सी. एक निश्चित विवरण के सामान का आयात करने का बीड़ा उठाया था और उसके आधार पर याचिकाकर्ता-फर्म से पैसा वसूलने के बाद वह याचिकाकर्ता-फर्म को उन सामानों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ता-फर्म को भारी और बार-बार होने वाली हानि में डाल दिया गया है। इसने रु. की आयात पात्रता अर्जित की है। 1,07,817.15 रुपये के अलावा अन्य राशि। 32,806 जिसे लेकर विवाद चल रहा है। एस.टी.सी. की कार्रवाई याचिकाकर्ता-फर्म को आयात की अनुमति नहीं देने के परिणामस्वरूप उसका व्यवसाय लगभग बंद हो गया है, जिससे कंपनी को वित्तीय रूप से प्रभावित होने के अलावा देश को विदेशी मुद्रा की हानि भी हुई है। इन तथ्यों पर याचिकाकर्ता-फर्म ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ या तो आयात लाइसेंस जारी करने या आयात सामग्री के लिए अनिवार्य रिट के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जो याचिकाकर्ता-फर्म के कारण गिर गया था। इसने एक घोषणा के लिए भी प्रार्थना की है कि यह प्रतिवादी नं.2, इंडेंट संख्या के अनुसरण में सामग्री का आयात प्राप्त करने के लिए। 618 और 625 याचिकाकर्ता-फर्म को जारी किए गए। यह भी प्रार्थना की गई कि उत्तरदाताओं की संविधान के विपरीत कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(11) केवल स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, प्रतिवादी नंबर 2, ने अपने उप विपणन प्रबंधक के माध्यम से एक लिखित बयान दायर किया है। इस प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं- (i) कि एस.टी.सी. कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है; (ii) कि याचिकाकर्ता-फर्म के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह प्रतिवादी के खिलाफ राहत के लिए इस याचिका को बरकरार नहीं रख सकती क्योंकि मामला प्रकृति में संविदात्मक था; (iii) कि याचिका मांगी गई राहत के बारे में अस्पष्ट है और; (iv) इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

(12) गुण-दोष के आधार पर सरकार की नीति और आदेश, मांगपत्र आदि देने के तरीके से संबंधित पैराग्राफों का उत्तर वही है जो सी.डब्ल्यू.पी. में दाखिल किया गया है। क्रमांक 4709-1975. यह तर्क दिया गया कि माल एस.टी.सी. द्वारा कभी वितरित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता-फर्म को न ही कभी कोई रेलवे रसीद दी गई। एस.टी.सी. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होने पर हमेशा शिपिंग दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है जब माल अभी भी खुले समुद्र में होता है और बिक्री उच्च-समुद्र की बिक्री होती है। सेवा शुल्क आदि के साथ अनुबंधित मूल्य के भुगतान के खिलाफ प्रस्तुति पर याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा शिपिंग दस्तावेजों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। अनुबंध में प्रावधान था कि डिलीवरी शिपिंग दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा आयातित माल की जानी थी जब माल भी पूर्ण भुगतान के विरुद्ध उच्च समुद्रों पर थे और बिक्री उच्च समुद्रों पर कच्चे ऊन, ऊनी कपड़ों की होगी, जिनकी सफाई और रख-रखाव की व्यवस्था संबंधित आयातक द्वारा की जानी थी। यह याचिकाकर्ता-फर्म थी, जिसने संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन किया था। यह उन पत्रों को लिखकर अपने दायित्वों से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था जिनकी मांग नहीं की गई थी और जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और जवाब नहीं दिया गया। चूंकि बिक्री सी.आई.एफ. थी। बिक्री की डिलीवरी शिपिंग दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होनी थी,

याचिकाकर्ता-फर्म ने इंडेंट नंबर 618/72 के दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया और खुद को आयातित माल का मालिक होने का दावा करते हुए वहां प्रवेश का बिल दाखिल किया। इंडेंट के बारे में नं. 625/72, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता-फर्म को एसटीसी के पक्ष में क्रेडिट का आंतरिक पत्र खोलने के लिए कहा गया था जो वह करने में विफल रहा। चूंकि यह क्रेडिट के आंतरिक पत्र में नहीं खुला था, इसलिए शिपिंग दस्तावेजों की प्रस्तुति पर भुगतान करना याचिकाकर्ता-फर्म की जिम्मेदारी थी और याचिकाकर्ता-फर्म ने उन दस्तावेजों का सम्मान करने से इनकार करके अनुबंध का उल्लंघन किया। एस.टी.सी. इस प्रकार याचिकाकर्ता-फर्म को उसकी आयात पात्रता के संबंध में सेवा प्रदान न करना उसके अधिकार क्षेत्र में था। एस.टी.सी. की पर्याप्त धनराशि। याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा अपने विशिष्ट इंडेंट और चयन के विरुद्ध आयात किए गए माल के परक्राम्य दस्तावेजों को वापस लेने में विफलता के कारण अवरुद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा एस.टी.सी. के अधिकारियों द्वारा कथित कोई भी मौखिक आश्वासना। हालांकि, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता-फर्म को समायोजित करने के लिए यह सूचित किया गया था कि यदि वह (याचिकाकर्ता-फर्म) से देय पूर्ण भुगतान पर दस्तावेजों का सम्मान करने के लिए तैयार है, तो एस.टी.सी. वैध के विरुद्ध ऊन की खरीद को प्रभावित कर सकता है। याचिकाकर्ता-फर्म के पास रिलीज ऑर्डर और आवंटन अप्रयुक्त और अप्रयुक्त पड़े हैं। लेकिन याचिकाकर्ता-फर्म ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। एस.टी.सी. सेवा न देने की अपनी कार्रवाई का बचाव किया लंबित रिहाई आदेशों के लिए याचिकाकर्ता-फर्म और यह स्थिति ली कि सीमा शुल्क अधिकारियों से माल को मंजूरी दिलाना याचिकाकर्ता-फर्म की जिम्मेदारी थी।

(13) बहस के दौरान श्री पी. आर. साहनी, उप विपणन प्रबंधक का एक हलफनामा। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नहरीकृत वस्तुओं से संबंधित आयात के बारे में कुछ बिंदुओं और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए 1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 4709 में दायर की थी। 25 नवंबर, 1967 के नीति वक्तव्य के मद्देनजर, कच्चे ऊन, ऊनी टॉप आदि का आयात केवल एस.टी.सी. के माध्यम से किया जा सकता है। माल का निर्यात करने से निर्यातक निर्माता निर्यात प्रोत्साहन के तहत अनुमत सीमा तक कच्चे माल का आयात करने के हकदार हो जाते हैं। सरकार की नीति और सीमा आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित की जाती है। रिलीज ऑर्डर मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा निर्यातक निर्माता को उसकी पात्रता की सीमा तक जारी किया जाता है और इसकी एक प्रति एस.टी.सी. को भेजी जाती है। रिलीज ऑर्डर का फॉर्म आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1955 के परिशिष्ट 34 में प्रदान किया गया है। यह आयात किए जाने वाले सामान का विवरण, सामान की मात्रा और उनके सीआईएफ को दर्शाता है। कीमत। एस.टी.सी. इन रिलीज ऑर्डरों के आधार पर आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक से आयात के लिए थोक लाइसेंस प्राप्त होता है। लाइसेंस की मूल प्रति जिसे "सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति" के रूप में जाना जाता है, एस.टी.सी. को भेजी जाती है। और इसकी कार्बन कॉपी जिसे "एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी" के रूप में जाना जाता है, एस.टी.सी. के शाखा कार्यालय को भेजी जाती है। बंदरगाह पर. साप्ताहिक खरीद बैठकें एस.टी.सी. के कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। नई दिल्ली में जहां रिलीज ऑर्डर देने वाले, विदेशी विक्रेताओं के स्थानीय एजेंट और एस.टी.सी. के अधिकारी मौजूद हैं। नई दिल्ली में एस. टी. सी. के कार्यालय में साप्ताहिक खरीद बैठकें आयोजित की जाती हैं जहाँ रिलीज ऑर्डर धारक, विदेशी विक्रेताओं के स्थानीय एजेंट और एस. टी. सी. के अधिकारी उपस्थित होते हैं। विदेशी विक्रेताओं और रिलीज ऑर्डर धारकों को अधिक प्रतिस्पर्धी खरीद और विदेशी मुद्रा के संरक्षण का सामना करना पड़ता है। विदेशी विक्रेता का चयन रिलीज ऑर्डर धारकों द्वारा किया जाता है जिसे एस.टी.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद रिलीज ऑर्डर धारक एस.टी.सी. को अधिकृत करते हुए एक विधिवत हस्ताक्षरित खरीद अनुरोध प्रस्तुत करता है। अपनी ओर से बिक्री पर बातचीत करने के लिए एना रिहाई आदेश भी उसे सौंप देती है। एस.टी.सी. फिर खरीद मांग के आधार पर रिलीज पुराने धारक के खाते पर रिलीज ऑर्डर धारक द्वारा चयनित विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ एक औपचारिक अनुबंध में प्रवेश करता है और अनुबंध की शर्तें

सी.आई.एफ. पर होती हैं। आधार. अनुबंध की प्रति रिलीज ऑर्डर धारक को एक कवरिंग लेटर के साथ भेजी जाती है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि अनुबंध उसकी ओर से किया गया है और वह विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव और बदलाव के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा शुल्क, ब्याज और बैंक शुल्क एस.टी.सी. द्वारा लिया जाएगा। उसे भी सूचित किया जाता है। एस.टी.सी. एक विदेशी साख पत्र खोलता है जो आम तौर पर रिलीज ऑर्डर धारक द्वारा उसके नाम पर एक आंतरिक साख पत्र द्वारा समर्थित होता है। विदेशी साख पत्र में अनुबंध का विवरण, उन पार्टियों का नाम जिनके लिए शिपिंग दस्तावेज़ तैयार किए जाते हैं और अन्य आवश्यक विवरण दिए जाते हैं। माल की शिपिंग के बाद विदेशी विक्रेता बैंक के माध्यम से दस्तावेज़ भेजता है जो 'परक्राम्य दस्तावेज़' होते हैं। दस्तावेज़ों में शामिल हैं (i) लदान का बिल, (ii) विनिमय का बिल, (iii) माल के विवरण वाले विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा तैयार किए गए चालान, (iv) बीमा पॉलिसी, (v) की विशिष्टता के संबंध में प्रमाण पत्र सामान और (vi) पैकिंग सूची। इन दस्तावेज़ों की अन्य कार्बन प्रतियां जिन्हें गैर-परक्राम्य दस्तावेज़ के रूप में जाना जाता है, एस.टी.सी. को भेजी जाती हैं। और रिलीज ऑर्डर धारक। एस.टी.सी., अपने बैंकों से परक्राम्य दस्तावेज़ एकत्र करता है और साथ ही माल दुलाई बिल और उसके द्वारा तैयार चालान भी एकत्र करता है, जिसमें सी.आई.एफ. शामिल होता है। माल का मूल्य, सेवा शुल्क, ब्याज सहित बैंक शुल्क और उन्हें रिलीज ऑर्डर धारक के बैंकर्स को एक विशिष्ट निर्देश के साथ भेजता है कि उन मामलों में धन की वसूली के बाद ही दस्तावेज़ जारी करें जहां आंतरिक क्रेडिट पत्र स्थापित नहीं किया गया है। रिलीज ऑर्डर धारक द्वारा इसके पक्ष में। रिलीज ऑर्डर धारक तब गंतव्य के बंदरगाह पर अपने समाशोधन एजेंट को परक्राम्य दस्तावेज़ भेजता है और माल के मालिक द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष प्रवेश का बिल दर्ज किया जाता है। मूल शिपिंग दस्तावेज़ याचिकाकर्ता-फर्म, यानी मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज द्वारा 3 अगस्त, 1972 को सेवानिवृत्त कर दिए गए थे, जब माल अभी भी पारगमन में था। माल वास्तव में 9 अगस्त, 1972 को बंदरगाह पर पहुंचा। याचिकाकर्ता द्वारा परक्राम्य दस्तावेज़ों को एसटीसी को केवल 9 अगस्त, 1975 को प्रविष्टि बिल और कस्टम चेक-एड चालान के साथ इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था कि वह डिमरेज की छूट के मामले को उठा सकता है।

(14) मेसारा लांबा इंडस्ट्रीज की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। आयात पात्रता के निर्धारण की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया गया था, अनुलग्नक पी. 38 और 39 के रूप में प्रस्तुत रिलीज आदेश की प्रतियों में शामिल था कि माल एसटीसी द्वारा आरटीई द्वारा आयातित माल में से याचिकाकर्ता-फर्म को भेजा गया था। याचिकाकर्ता-फर्म ने एस.टी.सी. के नाम पर लाइसेंस की एक प्रति, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-39 भी दाखिल की। और तर्क दिया कि आयातित माल में संपत्ति एस.टी.सी. की बनी रहेगी। जब तक कि उन्हें सीमा शुल्क द्वारा साफ़ नहीं कर दिया गया। एस.टी.सी. द्वारा बताई गई खरीद बैठकों की प्रक्रिया। इनकार कर दिया गया था और यह कहा गया था कि रिलीज ऑर्डर धारकों का विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के एजेंटों से सामना नहीं किया जाता है। नमूनों के साथ कोटेशन एस.टी.सी. द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। और रिलीज ऑर्डर धारक सामग्री का चयन करता है, और, इस प्रकार विदेशी आपूर्तिकर्ता, जिसके साथ एस.टी.सी. ऑर्डर देना होगा। इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी बैठकें एस.टी.सी. आयोजित की जाती हैं। माल को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम प्राधिकारी है। आयात टी विशेष रूप से लाइसेंसधारी द्वारा किया जाता है। अनुबंध सी.आई.एफ. है। जहां तक एस.टी.सी. संबद्ध है। एस.टी.सी. किस सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता-फर्मों के प्रतिनिधियों को रेलवे रसीदें जारी कर रहा है। आपूर्ति की गई। एस.टी.सी. द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 1970 के पत्र की एक प्रति। संलग्न था. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा माल की शिपिंग, परक्राम्य दस्तावेज़ भेजने और उनकी सेवानिवृत्ति के बारे में प्रक्रिया को स्वीकार किया गया था। यह जोड़ा गया कि विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भेजा गया मूल विनिमय बिल याचिकाकर्ता-फर्म को कभी नहीं भेजा गया था। माल को लाइसेंसधारी, यानी एस.टी.सी. द्वारा सीमा शुल्क से मंजूरी दे दी जाती है। कभी-कभी माल को एस.टी.सी. द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। और अपने स्वयं के बोझ को कम करने के लिए कुछ समय के लिए यह समाशोधन एजेंट को माल जारी करने का अधिकार देता है,

समाशोधन एजेंट केवल अधिकार प्राप्त होने पर ही माल जारी करवा सकता है और समाशोधन एजेंट एस.टी.सी. का एजेंट होता है। याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा दायर प्रविष्टि बिल पर केवल माल के मालिकों, यानी एस.टी.सी. द्वारा अधिकार पत्र जारी होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। आगे कहा गया कि दस्तावेजों को रिटायर करते समय याचिकाकर्ता-फर्म को यह जानकारी नहीं थी कि माल था या नहीं। बंदरगाह पर प्राप्त हुआ या नहीं।

(15) एस.टी.सी. याचिकाकर्ता-फर्मों के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करना चाहता था लेकिन हमारे द्वारा इस अनुरोध को अनुमति नहीं दी गई।

(16) दोनों सिविल रिट याचिकाओं में, उत्तरदाताओं की ओर से बहस के दौरान निम्नलिखित प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं: -

(1) यह कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है और इसके खिलाफ रिट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चलने योग्य नहीं है:

(1) इसमें शामिल मामले संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न नागरिक विवाद हैं जिनके लिए रिट उचित उपाय नहीं है;

(ii) भारत में विदेशी आपूर्तिकर्ता या उनके एजेंट जो आवश्यक पक्ष हैं, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है:

(iv) कि इस न्यायालय के पास सिविल रिट याचिका संख्या 4709/1975 में प्रतिवादी संख्या 6, पोर्ट ट्रस्ट बॉम्बे के खिलाफ मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है; और

(v) यह कि याचिका अस्पष्ट है क्योंकि दावा किया गया दावा विशिष्ट नहीं है।

(17) सिविल रिट याचिका संख्या 7409/75 में अनुलग्नक आर-2/1, एक मुद्रित पुस्तिका है जिसमें एसटीसी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है। एसोसिएशन के लेखों पर तर्क के आधार पर, एसटीसी, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील श्री आर.सी. डोगरा ने आग्रह किया है कि कंपनी न तो है कानून के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था और न ही कोई वैधानिक कार्य करती है, बल्कि यह केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, और इस प्रकार यह उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने आग्रह किया है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। इसने आयात नियंत्रण आदेश, 1955 अधिनियमित किया है और अधिनियम के तहत सभी नियमों और अधिसूचनाओं को "आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तिका नियम और प्रक्रिया 1973-74" नामक पुस्तक में समेकित किया गया है। इन नियमों और प्रक्रियाओं को समय-समय पर संशोधित किया गया है, इस आयात व्यापार नियंत्रण आदेश के भाग V की अनुसूची I में, क्रम संख्या 47 पर, ऊन के कच्चे, ऊनी टॉप सहित ऊनी अपशिष्ट घटिया और ऊनी लत्ता शामिल हैं।

आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसकी प्रति दोनों रिट याचिकाओं के अनुबंध पी-1 में है। इस नोटिस में लिखा है :-

"भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार नियंत्रण।

सार्वजनिक सूचना संख्या 172-आईटीसी (पीएन)/67. नई दिल्ली, 25 नवंबर, 1967।

(1) ऊनी कच्चा, ऊनी टॉप्स आदि (क्रमांक 47/वी) और (ii) सिंथेटी प्रोटीन कट फाइबर सहित स्टेपल फाइबर के लिए विषय आयात नीति [एस। क्रमांक 122(XV)/V]-अप्रैल, 1967-मार्च, 1968

अप्रैल की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक) की धारा III के भाग 'ए' में उपरोक्त उल्लिखित वस्तु के आयात के लिए इंगित नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 1967-मार्च, 1968.

2 अब यह निर्णय लिया गया है कि कच्चे ऊन, ऊन टोपा आदि के सभी आयात को रद्द कर दिया जाए। (क्रमांक 47/वी) और पॉली-एस्टर फाइबर सहित सभी सिंथेटिक गैर-सेलूलोज़ फाइबर [एस. संख्या, 122 (XV) - VI राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली के माध्यम से पंजीकृत निर्यातकों के लिए नीति के तहत किए गए आयात सहित।

3. कच्चे ऊन का आयात होगा। हालाँकि, वर्तमान में सी.सी. के विरुद्ध तलाशी इकाइयों को अनुमति जारी रहेगी। पी.एस. कंधी करने के बाद ऊन के शीर्ष के रूप में निर्यात के उद्देश्य से कच्चे ऊन के आयात के लिए जारी किया गया,

4. इन वस्तुओं के लिए आयात नीति को तदनुसार संशोधित माना जा सकता है।

(एसडी.) पी. डी. काबेस्कर, मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक",

इस आदेश के बाद, याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता के अनुसार, यह केवल एस.टी.सी. है, जो कच्चे ऊन, ऊनी टॉप, रैग्स इत्यादि के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। जैसा कि एस.टी.सी. केंद्र सरकार की कैनालाइजिंग योजना के तहत कपड़े, कच्चे ऊन, ऊनी टॉप आदि का आयात करने वाली एकमात्र एजेंसी है, यह कानून के तहत सरकारी कार्यों का निर्वहन कर रही है। उस स्थिति में एस.टी.सी. याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता के अनुसार, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 में निहित "प्राधिकरण" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एस.टी.सी. एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जिसके सभी शेयर भारत सरकार के पास हैं और इसका प्रबंधन भी सरकार द्वारा किया जाता है।

(18) सबकाजीत तियोआरी बनाम भारत संघ, आदि में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एक पक्ष था जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। भारत के प्रधानमंत्री सोसायटी के पदेन अध्यक्ष हैं और शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार शासी निकाय के पदेन सदस्यों के अलावा किसी भी समय किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संबंधित सभी मामले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन हैं। इन तथ्यों पर मामले में यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद एक प्राधिकरण है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में निहित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने (पैरा 4 में) निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त किया: -

"उपरोक्त विशेषताओं को उद्धृत करते हुए, यह तर्क दिया गया कि ये संकेत देंगे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद वास्तव में सरकार की एक एजेंसी थी यह तर्क निराधार है। सोसायटी का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, या जीवन बीमा निगम या औद्योगिक वित्त निगम जैसा कोई वैधानिक चरित्र नहीं है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगमित एक सोसायटी है। यह तथ्य कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है या कि सरकार शासी निकाय के लिए नामितों की नियुक्ति करती है या कि सरकार सदस्यता समाप्त कर सकती है, इस तथ्य से अधिक कुछ स्थापित नहीं होगा कि सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का प्रचार, मार्गदर्शन और सहयोग, विशिष्ट अनुसंधानों का संस्थान और वित्तपोषण, किसी व्यापार में विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मौजूदा संस्थानों के विशेष संस्थानों या विभागों को स्थापना या विकास और सहायता, देश में उद्योगों के विकास के लिए परिषद के तत्वावधान में किए गए शोधों के परिणाम का उपयोग एक जिम्मेदार तरीके से किया जाता है। "

(19) प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम सी.वी. इमानुअल और अन्य (21) इसी तरह के तथ्यों पर, इसे निम्नानुसार माना गया था:

"कंपनी एक गैर-वैधानिक निकाय है और कंपनी अधिनियम के तहत शामिल है, उस पर किसी कानून द्वारा कोई वैधानिक सार्वजनिक कर्तव्य नहीं लगाया गया है, जिसके संबंध में एक परमादेश के माध्यम से प्रवर्तन की मांग की जा सकती है, न ही इसमें कोई प्रावधान था कर्मचारियों को सार्वजनिक कर्तव्य के किसी भी वैधानिक प्रवर्तन के लिए कोई भी कानूनी अधिकार है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में सही था कि कोई रिट याचिका नहीं। किसी परमादेश के लिए या परमादेश की प्रकृति में कोई आदेश कंपनी के खिलाफ नहीं हो सकता।"

उस फैसले में यह भी कहा गया था:

पीठ ने कहा, "आदेश के रूप में, एक व्यक्ति, निगम या एक निम्न न्यायाधिकरण को एक आदेश दिया जाता है, जिसमें उसे या उन्हें उसमें निर्दिष्ट एक विशेष काम करने की आवश्यकता होती है, जो उसके या उसके कार्यालय से संबंधित है और एक सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति या प्राधिकारी पर वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है, वह एक सार्वजनिक अधिकारी या एक आधिकारिक निकाय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक परमादेश किसी अधिकारी या सोसाइटी को जारी कर सकता है कि वह उसे उस कानून की शर्तों का पालन करने के लिए मजबूर करे जिसके तहत या जिसके द्वारा सोसाइटी का गठन या शासन किया जाता है और कंपनियों या निगमों को भी अपने उपक्रमों को अधिकृत करने वाले कानूनों द्वारा उन पर लगाए गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए। सार्वजनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए एक कानून द्वारा गठित कंपनी के खिलाफ भी एक आदेश होगा।

सभाजीत तिवारी के मामले (ऊपर) में प्रागा टूल्स के मामले में फैसले का पालन किया गया हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम बिहार राज्य और एस. एल. अग्रवाल बनाम महाप्रबंधक, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का उल्लेख करते हुए सभाजीत तिवारी के मामले में यह पाया गया कि इन कंपनियों को उन मामलों में सरकार से स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था और निगम से संबंधित कानून द्वारा, इन्हें सरकार के विभाग नहीं माना जा सकता था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक प्राधिकरण नहीं माना गया था।

(20) याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाई गुप्ता ने सुखदेव सिंह और अन्य बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी और अन्य आदि का उल्लेख किया, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 में निर्दिष्ट एक प्राधिकरण माना गया था। सभाजीत तिवारी के मामले में टिप्पणियों के अनुसार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तुलना किसी कंपनी से नहीं की जा सकती थी। याचिकाकर्ता-फर्म के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत सुखदेव सिंह का मामला अलग है और इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। यहां तक कि सुखदेव सिंह के मामले में भी, पैरा 25 में एक कंपनी और एक वैधानिक निकाय के बीच अंतर निम्नानुसार किया गया था: -

एक कंपनी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियम और विनियम बनाती है। दूसरी ओर एक सांविधिक निकाय ऐसे निकायों का निर्माण करने वाले कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा और उनके तहत नियम और विनियम बनाता है।

* * * * *

एक कंपनी तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कि उसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगमित नहीं किया जाता है। एक कंपनी तब तक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करती है।

* * * * *

एक कानून द्वारा बनाए गए निगम के मामले में नियम और विनियम बनाने की शक्ति का स्रोत कानून ही है। कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी अधिनियम द्वारा नहीं बनाई जाती है, बल्कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू होती है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि यह कानून द्वारा नहीं बनाया गया है। यह कानून की शर्तों के अनुसार बनाया गया एक निकाय है।

(21) याचिकाकर्ता-कंपनियों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर बनाम मोहन लाल और अन्य (6) में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें राजस्थान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में निहित विद्युत बोर्ड को "राज्य" माना गया था। मोहन लाल के मामले की विशिष्ट विशेषताएं सुखदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में देखी गईं और इसे निम्नानुसार माना गया

"राजस्थान बिजली बोर्ड मामले में, यह कहा गया था कि निर्देश देने की शक्ति, जिसकी अवज्ञा एक आपराधिक अपराध के रूप में दंडनीय होनी चाहिए, अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर निकाय को एक प्राधिकरण के रूप में चिह्नित करने के कारणों में से एक प्रस्तुत करेगी। नियम या विनियम बनाने और उन्हें प्रशासित या लागू करने की शक्ति अनुच्छेद 12 में विचार किए गए अधिकारियों के तत्वों में से एक होगी। अनुच्छेद 12 में परिकल्पित प्राधिकरणों को राज्य कार्रवाई के साधन के रूप में वर्णित किया गया है।

इसलिए, मोहन लाल के मामले का निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता है।

(22) धरम पाल सोनी बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7) में, जालंधर सेंट्रल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स स्टोर लिमिटेड के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी, जो पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961

के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत थी। इस न्यायालय की एक डिविजन बेंच द्वारा इसे निम्नानुसार माना गया था-

"प्रतिवादी नंबर 2, एक अन्य सामान्य सहकारी समिति की तरह सोसायटी पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि केवल अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ऐसे निगम को किसी कानून द्वारा बनाया गया नहीं कहा जा सकता है। न ही प्रतिवादी संख्या 2 कोई संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकारी है।"

(23) याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाई गुप्ता ने स्वीकार किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय या इस न्यायालय के किसी भी मामले पर अपना हाथ नहीं रख सकते हैं, जिसका उनके तर्क के समर्थन में एक समिति पर सीधा असर पड़ता है। वे केवल के. एल. मैथ्यू और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दे सकते थे। इस मामले में समान आधारों पर जैसा कि भारतीय काजू निगम लिमिटेड को काजू के आयात और फिर अंतिम उपयोगकर्ताओं को इसके आवंटन के लिए राज्य व्यापार निगम लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था। उस मामले में याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर आवंटन से इनकार कर दिया गया था कि वे संबंधित अधिसूचना और आदेशों में उल्लिखित तिथियों पर काजू का आयात नहीं कर रहे थे। उस मामले में, विवाद के तहत मुख्य बिंदु यह था कि आवंटन प्रणाली मनमाना, काजू निगम की शक्तियों से परे और भेदभावपूर्ण थी। काजू निगम ने एक याचिका दायर की कि यह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और इसके खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती है।

(24) सरकार ने आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत और आयात आदेश के तहत काजू के आयात और इसके वितरण के मामले में खुले सामान्य लाइसेंसिंग प्रणाली को वापस लेने के बाद कुछ शुल्कों का निर्वहन करने का बीड़ा उठाया था! इस वस्तु का आयात। यह कार्य जिसे उसे वैधानिक रूप से करना है, काजू निगम को सौंपा गया था। इस प्रकार काजू निगम, विद्वान न्यायाधीश के विचार के अनुसार, अपने प्रतिवेदन और आवंटन के मामले में कानून के तहत एक सरकारी कार्य कर रहा था। काजू निगम के मामलों का प्रशासन भारत सरकार की चिंता का विषय है। निगम का कानूनी और लाभकारी स्वामित्व भारत सरकार में निहित है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कच्चे काजू के आवंटन के इस कर्तव्य के निर्वहन में प्रत्यर्थियों को, उस मामले में, आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम और आयात नियंत्रण आदेश और नीतिगत विवरण का पालन करना था और यदि इस कर्तव्य के निर्वहन में प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ था तो पीड़ित पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

(25) के. एल. मैथ्यू के मामले में अंतर की बात और मामला यह है कि मौजूदा मामले में एस.टी.सी. द्वारा लत्ता या ऊन का कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है। आवेदकों द्वारा किए गए निर्यात के आधार पर किसी अन्य एजेंसी द्वारा आवंटन किया जाता है। यह लाइसेंसिंग प्राधिकारी है न कि एस.टी.सी. जो रिलीज ऑर्डर जारी करने के लिए आयात पात्रता निर्धारित करता है और आवंटन करता है। नहरीकृत वस्तुओं के रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद एस.टी.सी. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से केवल आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित उनकी आयात पात्रता के विरुद्ध रिलीज ऑर्डर धारकों द्वारा चुनी गई सामग्री का आयात करता है। यह केवल खरीदार और विक्रेताओं को एक साथ लाने का काम करता है और चयनित वस्तुओं के आयात के लिए एक नाली पाइप के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, इसे सौदे की प्रकृति और पार्टियों के इरादे की जांच करके विदेशी मुद्रा आदि की बर्बादी के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय करने होंगे। काजू कॉरपोरेशन की तरह यह व्यवसाय में

व्यक्तियों को आवंटन करने या आयात पात्रता के लिए उनके दावों को अस्वीकार करने में सरकार के कार्यों का आयात या निर्वहन नहीं करता है। यह केवल उन व्यक्तियों के लिए काम करता है जिनके पास केंद्र सरकार द्वारा जारी वास्तविक रिहाई आदेश हैं और सेवा शुल्क के रूप में 2/2J प्रतिशत का एहसास होता है। मेरे विचार से, के एल मैथ्यू के मामले (सुप्रा) के तथ्य समान नहीं हैं और वर्तमान मामला सभाजीत तिवारी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत आता है। मामले में दूसरा बिंदु यह है कि एस.टी.सी. का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, सभाजीत तिवारी के मामले में फिर से कवर किया गया है। उस फैसले के मद्देनजर यह नहीं माना जा सकता कि एस.टी.सी. वास्तव में सरकारी वैधानिक या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है।

(26) निगम जो कानून द्वारा बनाए गए हैं और वैधानिक कार्य करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। एस.टी.सी. कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह न तो iCompanies अधिनियम का निर्माण है और न ही आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का। यह कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है, इसका अपना ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख हैं, यह निदेशक मंडल द्वारा शासित है और अपना काम कर रहा है। खुद का व्यवसाय। उस क्षमता में यह कच्चे ऊन, टॉप, लत्ता आदि और कई अन्य संबद्ध वस्तुओं के आयात को संभालने का अतिरिक्त कर्तव्य करता है जैसा कि आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा इसे सौंपा गया है। एमएफएस दारुका एंड कंपनी बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पक्ष था। उस मामले में विवादित नोटिस के तहत अभ्रक के निर्यात को योजना के तहत करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें खनिजों और खनिजों के माध्यम से निर्मित और निर्मित अभ्रक, मिकानाइट, पुनर्गठित अभ्रक, अभ्रक पाउडर और अभ्रक कागज को छोड़कर, सभी ग्रेड और अभ्रक की विविधता के निर्यात को शामिल किया गया था। मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उस मामले में विवादित नोटिस के खिलाफ चुनौती छह गुना थी; पहला यह कि यह एक नहरकरण योजना नहीं थी; दूसरा यह कि योजना ने एक अनुचित प्रतिबंध लगाया जहां तक कि इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का नुकसान, लाभ का नुकसान होता है और अनुबंध विदेशी खरीदारों को अनुबंध से बचने और अनुबंध के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा करने में सक्षम बनाता है; तीसरा आपातकाल की घोषणा के बाद यह पता लगाना था कि क्या नहरकरण योजना को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत बनाया जाना था; चौथा योजना ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया; पांचवां 24 जनवरी, 1972 का निर्धारण, योजना के लागू होने की तारीख के रूप में मनमाना था और छठा F.A.S. का एक प्रतिशत शुल्क लगाना था। बिना किसी संबंधित लाभ प्रदान किए मूल्य एक अनुचित प्रतिबंध था और वास्तव में एक कर था। इस मामले में याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा हमले का इनमें से कोई भी आधार नहीं उठाया गया है और यह मामला हाथ में मामले को लागू करने के लिए आकर्षित नहीं है।

(27) भारत के संविधान में "अधिकार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। रिट जारी होने से पहले, जैसा कि इस मामले में प्रार्थना की गई है। एस.टी.सी. के विरुद्ध याचिकाकर्ता-फर्मों को तीन चीजें साबित करने की आवश्यकता है: (i) कि यह एक वैधानिक निकाय है और इसका निर्माण एक कानून के तहत होता है, जिसमें इससे उत्पन्न होने वाली शक्तियां और दायित्व होते हैं और इसके कार्य कानून द्वारा शासित होते हैं या इसके तहत बनाए गए नियम: (बी) कि यह सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है और (iii) कि एक वैधानिक नियम का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी। एस.टी.सी. किसी कानून द्वारा नहीं बनाया गया है। यह किसी भी वैधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और न ही किसी कानून से उत्पन्न किसी दायित्व का निर्वहन करता है। यह केवल अपने द्वारा आयोजित खरीद बैठक में रिलीज ऑर्डर-धारकों द्वारा चुनी गई सामग्री का आयात करता है और सेवा शुल्क लेता है जो 2.25 प्रतिशत है। इसके द्वारा कोई भी शासकीय कार्य संपादित नहीं किया जा रहा है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं

ने सी.डब्ल्यू.पी. में स्थानांतरित होने के बाद कस्टमा अधिकारियों से माल खाली कराने में आरोप लगाया था, यह विफल रहा। क्रमांक 4709/75 तथा इंडेंट क्रमांक 618/75 के विरुद्ध सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 238/75, किसी भी वैधानिक कर्तव्य या नियम के उल्लंघन का प्रभाव नहीं रखता है। ऊपर दी गई पहली दो आवश्यकताएं व्यक्ति या निकाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में निहित अधिकार का रंग देती हैं। तीसरा, आम तौर पर, पहले दो से आता है, और मुझे नहीं पता कि एस.टी.सी. द्वारा कोई वैधानिक उल्लंघन किया गया है या नहीं। एस.टी.सी. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख के साथ पंजीकृत कंपनी है। इसके चारों ओर एक कॉर्पोरेट कुँआ है जिसे छेदा नहीं जा सकता। यह न तो कोई वैधानिक निकाय है और न ही इसके कार्य सरकारी या सार्वजनिक हैं। यह गुप्त सौदों पर नज़र रखता है ताकि इनका परिणाम विदेशी मुद्रा में न हो। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में निहित प्राधिकरण के रंग और जाल का अभाव है और इसके परिणामस्वरूप इसके खिलाफ एक रिट नहीं है।

(28) याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता का तर्क कि एस.टी.सी. सरकारी और सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित किया जाता है, इसका उत्तर सभाजीत तिवारी के मामले (सुप्रा) में दिया गया है। सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4709/1975 के साथ संलग्न मेमोरन दम और एसोसिएशन के लेख, एक्ज़िबिट आर. 2/1 दर्शाते हैं कि आयात और निर्यात और वस्तुओं को कैनालाइज़ करना एस.टी.सी. द्वारा किया गया या करने का एकमात्र कार्य या व्यवसाय नहीं है। उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई पहली प्रारंभिक आपत्ति महत्वपूर्ण है और इस मामले में कायम है।

(29) अगली प्रारंभिक आपत्ति यह है कि ये मामले संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न नागरिक विवादों से जुड़े हैं/हैं और इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। रिलीज ऑर्डर धारक को एस.टी.सी. के माध्यम से अपनी पसंद का सामान आयात करना है। उत्तरदाताओं के अनुसार अनुबंध सी.आई.एफ. था। अनुबंध और इंडेंट और अनुलग्नक आर. 2/2 की प्रतिलिपि द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. में दिखाया गया है। 4709/75 एवं आर. 2/3 सी.डब्ल्यू. क्रमांक 238/75 में। डिलीवरी ऊंचे समुद्र में डिलीवरी होनी थी। मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4709/1975 एवं मेसर्स हरबंस एंड कंपनी सी.डब्ल्यू.पी. 238/1975 (इंडेंट संख्या 618/72 के मामले में) ने दस्तावेजों को तब हटा दिया जब माल अभी भी खुले समुद्र में था। बहस के दौरान, हालांकि इसे रिट याचिकाओं में आधार के रूप में नहीं लिया गया था, याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा दावा किया गया था कि उन्हें निरीक्षण पर माल को अस्वीकार करने का अधिकार था क्योंकि ये विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। इस अधिकार का एस.टी.सी. द्वारा विरोध किया गया है। तथ्य का एक और विवादित प्रश्न है (हालांकि इसे इन याचिकाओं में उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है), क्या एस.टी.सी. याचिकाकर्ता-फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था या नहीं। मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज में तथ्य का एक और विवादित प्रश्न है कि किससे, यानी एस.टी.सी. मेसर्स कैमल निटिंग एंड टेक्सटाइल मिल्स के लिए, याचिकाकर्ता-फर्मों को मेसर्स कैमल निटिंग एंड टेक्सटाइल मिल्स, प्रतिवादी नंबर 7 की ओर से भुगतान किए गए पैसे का शुल्क लेना है। रखे गए माल की खरीद आवश्यकताओं से तथ्यों के विवादित प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा- आयात के लिए एस.टी.सी. पर फर्मों।

(30) हर्षवर्धन और अन्य बनाम उप आबकारी और कराधान आयुक्त और अन्य में पंजाब राज्य में शराब के कुछ अनुबंधों की नीलामी की गई थी। याचिकाकर्ताओं की बोलियों को स्वीकार कर लिया गया और उनके नाम पर शराब के ठेके आवंटित किए गए। कुछ समय तक व्यवसाय करने के बाद ठेकेदारों ने कुछ शर्तों आदि को लागू करने के लिए वित्तीय आयुक्त की शक्तियों को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय में अपील पर रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उठाई गई थी कि संविदात्मक

दायित्व को लागू करने के लिए कोई रिट दायर नहीं की जा सकती है। आपत्ति को बरकरार रखते हुए यह देखा गया -

पीठ ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य स्वेच्छा से किए गए दायित्वों से बचना नहीं है। "

इसी तरह डी.एल.एफ. हाउसिंग कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य के मामले में रिट याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि इसमें सबूतों के आधार पर कानून और तथ्य का जटिल सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि रिट कोर्ट ऐसी राहत पाने के लिए उचित मंच नहीं है।

(31) याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने डी.एफ.ओ. में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। दक्षिण खीरी एवं अन्य बनाम राम सनेही सिंह (12)। उस मामले में तथ्य इस प्रकार थे-

"वन अधिकारी द्वारा आयोजित एक नीलामी में, इस अपील में प्रतिवादी राम सनेही सिंह ने दक्षिण के मैलानी और गोला रेंज में वन क्षेत्र से 1 नवंबर, 1965 से 31 अक्टूबर, 1966 की अवधि के लिए लकड़ी काटने का अधिकार खरीदा। खीरी। 10 जनवरी, 1967 को प्रभागीय वन अधिकारी, दक्षिण खीरी प्रभाग, सायन ने एक आदेश पारित किया कि 1965-66 सीज़न के आवंटन में 29 अक्टूबर, 1966 के "टैली के विरुद्ध" स्लीपर "गलत" थे क्योंकि वे नवंबर 1966 के महीने में कटौती की गई थी, रद्द कर दी गई है और स्लीपरों को "हैमर-मार्क्स को रद्द करने के बाद टैली के खिलाफ पारित किया गया है और 1966-67 सीज़न के लिए आवंटन के खिलाफ फिर से निरीक्षण किया गया है।" उस आदेश के अनुसार, प्रतिवादी जिस लकड़ी का दावा कर रहा है, वह वास्तव में उसके द्वारा 29 अक्टूबर 1966 के मिलान के तहत वन अधिकारियों की मंजूरी के साथ हटा दी गई थी, ऐसा माना जाएगा जैसे कि इसे नवंबर, 1966 में हटा दिया गया था।"

इन तथ्यों पर यह निर्णय लिया गया:-

"जहां वैधानिक शक्तियों के साथ निवेश किए गए सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, रिट याचिका बनाए रखने योग्य है, भले ही राहत का अधिकार अनुबंध के कथित उल्लंघन से उत्पन्न हो।"

(32) प्रकरण में एस.टी.सी. वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है और न ही उसे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस बिंदु पर राम सनेही सिंह का मामला (सुप्रा) अलग है और इस मामले में लागू नहीं होता है। एस.टी.सी. मेरे विचार में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 के अनुसार एक प्राधिकरण भी नहीं है। याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने तर्क दिया कि कोई संविदात्मक दायित्व नहीं हैं, लेकिन याचिकाकर्ता आयात के अपने अधिकार को लागू कर रहे हैं जिसके लिए उनके पास रिलीज ऑर्डर है क्योंकि वे एसटीसी के अलावा किसी भी चीज का आयात नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को आयात पात्रता के विरुद्ध रिहाई आदेश देने से इंकार नहीं किया गया था, लेकिन माल वास्तव में सीमा शुल्क द्वारा जारी नहीं किया गया था, जो मांगपत्र के विरुद्ध आयात किया गया था। एस.टी.सी. की राशि के रूप में इंडेंट संख्या 625/72 के माल के मामले में एस.टी.सी. अवरुद्ध कर दी गई है। लंबित रिलीज ऑर्डर के लिए मेसर्स हरबंस एंड कंपनी को सेवा देने से इनकार कर दिया। एस.टी.सी. के साथ विवाद माल बंबई के बंदरगाह पर उतरने के बाद उत्पन्न हुआ और याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा दावा किए गए अधिकार अनुबंध से उत्पन्न हुए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता-फर्म आयात करने के अपने अधिकार को लागू नहीं कर

रही हैं, बल्कि अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मामलों को लागू कर रही हैं। एस.टी.सी. द्वारा संविदात्मक दायित्व का कोई भी उल्लंघन। इस मामले में, यदि कोई है तो यह याचिकाकर्ता-एम्स को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार को लागू करने का अधिकार नहीं देता है। एस.टी.सी. की अनिच्छा के संबंध में लंबित रिलीज ऑर्डर में माल के आयात के लिए याचिकाकर्ता-फर्मों को सेवा प्रदान करने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि यह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है।

(33) तीसरी आपत्ति यह है कि क्या विदेशी आपूर्तिकर्ता एक आवश्यक पक्ष हैं? यह तर्क दिया गया है कि एस.टी.सी. स्टॉक और बिक्री के आधार पर माल का अनुबंध नहीं करता है, बल्कि केवल स्वामित्व के दस्तावेजों को प्रसारित करता है, जो कि उत्तरदाताओं के वकील श्री आर.सी.डोगरा के अनुसार, बिक्री नहीं है। श्री आर. सी. डोगरा ने आगे कहा कि यदि सामान याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा ऑर्डर किए गए सामान के विवरण का उत्तर नहीं देता है तो विदेशी आपूर्तिकर्ता या भारत में उनके एजेंट, जिनसे खरीदारी की गई थी, आवश्यक पक्ष हैं और उनके गैर-जॉइन्डर याचिका के लिए घातक है। याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाई गुप्ता ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया है। याचिकाकर्ता-फर्मों ने विदेशी विक्रेताओं या भारत में उनके एजेंटों के खिलाफ किसी राहत की मांग नहीं की है। चूंकि माल की अस्वीकृति का मुद्दा याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा रिट याचिकाओं में नहीं उठाया गया था और याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा याचिका में भारत में अपने एजेंटों के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया था, इसलिए वे आवश्यक पक्षकार नहीं थे। इन याचिकाओं का उचित निर्णय।

(34) पोर्ट ट्रस्ट बॉम्बे, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से, सिविल रिट याचिका संख्या 4709/75 में, एक आपत्ति उठाई गई थी कि इस प्रतिवादी के खिलाफ इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ। न्यायालय, जहां कार्रवाई के कारण का कोई भाग उत्पन्न होता है, उसके पास कारण की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। इस मामले में दोनों याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा भुगतान अपने बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों को रिटायर करके लुधियाना में किया गया था। इस प्रकार इस न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है,

(35) दलीलों के दौरान हमें याचिका की अस्पष्ट प्रकृति या मांगी गई राहत को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया, हालांकि संकीर्ण प्रारंभिक आधार पर रिट को खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने पक्षों को पूरी तरह से सुना है ये खूबियां हम तय करेंगे।

(36) याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने तर्क दिया है कि कच्चे ऊन, ऊनी टॉप और लत्ता आदि का आयात एस.टी.सी. के माध्यम से किया गया था। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा, 1967 में याचिका के आदेश प्रति अनुलग्नक पी-1 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 3 के तहत आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया था। इस वैधानिक अधिनियम और आदेश के तहत एस.टी.सी. के अलावा कोई भी नहीं। नहरीकृत ऊनी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। "लाइसेंस" और "लाइसेंसधारी" की परिभाषाओं और आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश, 1955 (इसके बाद आदेश कहा जाएगा) के खंड 3(1) के साथ, एसआईटी.सी, लाइसेंसधारी है और इस आधार पर यह इन वस्तुओं का आयात करता है प्रिंसिपल या मालिक और एजेंट के रूप में नहीं। श्री कुलदीप सिंह. प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस तर्क का विरोध किया है, उनका तर्क यह है कि एस.टी.सी. एक एजेंसी है, जो अधिनियम और उसके तहत लागू आदेशों और नियमों की योजना और स्थापित प्रथा के अनुसार, कैनालाइज्ड माल का आयात स्वयं नहीं करती है, बल्कि रिलीज ऑर्डर धारकों के एजेंट के रूप में करती है, जो प्रस्तावित सामग्री का चयन करने के बाद खरीद

बैठकों में विदेशी आपूर्तिकर्ता, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जाने वाले सामानों का इंडेंटेशन करते हैं और इसे देश में आयात करते हैं।

(37) अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात, निर्यात या आवाजाही या नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंध लगाने की शक्तियां दी गई हैं। उन के कच्चे, ऊन के शीर्ष आदि के सभी आयातों को सीमित करने की सार्वजनिक सूचना, प्रतिलिपि ए (नेक्सचर पी-1), पहले पुनः प्रस्तुत की गई है। आदेश की धारा 2 (एएएए) और धारा 2 (बी) में दिए गए शब्दों "लाइसेंस" और "लाइसेंसधारी" की परिभाषा इस प्रकार है: -

"लाइसेंस" में इस आदेश के तहत जारी सीमा शुल्क निकासी परमिट शामिल है;

"लाइसेंसधारी का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे इस आदेश के तहत लाइसेंस या कस्टमा क्लियरेंस परमिट प्रदान किया गया है"।

आदेश का खंड 3(1) भी संदर्भ के लिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"इस आदेश में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार या किसी अधिकारी द्वारा दिए गए लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट के तहत और उसके अनुसार अनुसूची I में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी सामान का आयात नहीं करेगा। अनुसूची II में निर्दिष्ट।"

याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता के अनुसार, कोई भी निजी रिलीज ऑर्डर धारक सीधे माल का आयात नहीं कर सकता जब तक कि सीमा शुल्क निकासी की अनुमति न हो। उसके नाम पर जारी किया जाता है।

(38) ऊनी वस्तुओं का प्रत्येक निर्माता जो अपनी उपज का निर्यात करता है, उसे अपने वास्तविक निर्यात के विरुद्ध नियमों के अनुसार केंद्र सरकार से आयात का अधिकार मिलता है। फॉर्म में आयात पात्रता जो निर्यातक को एस.टी.सी. पर जारी की जाती है। इसे रिलीज ऑर्डर के रूप में जाना जाता है और इसके धारक को रिलीज ऑर्डर धारक के रूप में जाना जाता है। एस.टी.सी. खरीद-बैठकों की व्यवस्था करता है जहां विदेशी विक्रेता अपने स्थानीय एजेंटों के माध्यम से बिक्री के लिए सामान पेश करते हैं। रिहाई आदेश धारक एस.टी.सी. के अधिकारियों की देखरेख में। सामग्री का चयन करें और खरीद अनुरोध एस.टी.सी. के पास रखें। आयात करने के लिए, एस.टी.सी. फिर अपने बैंकरो के माध्यम से उनके नाम पर अपरिवर्तनीय साख पत्र स्थापित करने के बाद विदेशी विक्रेताओं से इंडेंट के माध्यम से चयनित सामान खरीदता है। क्रय मांग जिसके आधार पर माल की खरीद का अनुबंध किया जाता है वह सी.आई.एफ. है। अनुबंध। यह वह प्रक्रिया है जिसे मैंने पक्षों के वकील से समझा है जैसा कि बहस के दौरान बार में कहा गया था और जिसका पालन रिलीज ऑर्डर धारकों और एस.टी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

(39) 1972 में मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज (1975 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4709 में) ने ऐसी खरीद बैठक में भाग लिया, माल का चयन किया और एस.टी.सी. के साथ खरीद की मांग रखी, जिसकी प्रतिलिपि ऊनी की खरीद के लिए एक नेक्सचर आर-2/4 है। चिथड़े। इस खरीद मांग में जो डिलीवरी का सुझाव दिया गया था वह 'उच्च समुद्र' डिलीवरी थी और शिपमेंट अवधि पर 'जितनी जल्दी हो सके' जोर दिया गया था। एस.टी.सी. 5 फरवरी, 1972 को मेसर्स वाई. निशिदा एंड कंपनी लिमिटेड, ओकचामा, जापान को इंडेंट नंबर 7014/72 दिया गया (याचिका में अनुलग्नक पी-2 की प्रतिलिपि बनाएँ)। इस इंडेंट में सामान का जो

विवरण दिया गया था वह था "पुराने ऊनी कपड़े।" अधिकतर हल्के रंग. व्यावसायिक रूप से सभी ऊना।" अन्य विवरणों के अलावा खरीदार का उल्लेख एस.टी.सी.. ए/सी, एम/एस लांबा इंडस्ट्रीज, लुधियाना के रूप में किया गया था। इस मांगपत्र की प्रति एस.टी.सी. द्वारा भेजी गई थी। मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज को, दिनांक 15 फरवरी 1972 के पत्र द्वारा (याचिका के अनुलग्नक पी-3 की प्रतिलिपि बनाएँ)। इस पत्र में लिखा था कि "खरीदी आपकी ओर से की गई है." इसमें आगे कहा गया, "कृपया ध्यान दें कि विदेशी मुद्रा की दर में किसी भी बदलाव के लिए अंतर के भुगतान की देनदारी, यदि कोई हो, आपकी होगी।"

(40) इसी प्रकार, 15 फरवरी, 1972 को मेसर्स हरबंस एंड कंपनी (सी.डब्ल्यू.पी. नं. 238/1975) ने एस.टी.सी. के कहने पर आयोजित खरीद बैठक में भाग लिया। और सामग्री का चयन करने के बाद सामान, यानी ऊनी कपड़े खरीदने का ऑर्डर दिया। इनमें से इंडेंट नंबर 625/72 (जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक आर. 2/3 है) पर खरीद मांग उत्तरदाताओं द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई थी। यह एक सी.एल.एफ. था। उच्च समुद्र डिलीवरी के लिए अनुबंध। एस.टी.सी. इंडेंट नंबर 618, दिनांक 16 रखा गया। फरवरी, 1972, मेसर्स सोसायटी पर। ऊनी कपड़ों की खरीद के लिए वैलेंटिनी 3-5-7 प्रेट (इटली) के माध्यम से बाटैट। दूसरा इंडेंट नंबर 625, दिनांक 7 फरवरी, 1972, ऊनी कपड़ों के लिए मेसर्स मिनियापोलिस एक्सपोर्ट कंपनी, मिनियापोलिस, मिनेसोटा यू.एस.ए. को दिया गया था। सामान का विवरण "पुराने मूल ऊनी वस्त्र पेस्टल रंग" था। इन दोनों इंडेंटों में खरीदार का उल्लेख मुख्य विपणन प्रबंधक, एस.टी.सी., नई दिल्ली ए/सी के रूप में किया गया था; मेसर्स हरबंस एंड कंपनी, लुधियाना, फरवरी, 1972, मेसर्स सोसायटी पर। मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज के मामले में वैलेंटिनी 3-5-7 प्रेट के माध्यम से बाटैट।

(41) इंडेंट संख्या 7014/72 और 618/72 का माल विदेशी विक्रेताओं द्वारा भेजा गया था। दस्तावेज़, यानी, (i) लदान का बिल, (ii) विनिमय का बिल, (iii) चालान, (iv) बीमा पॉलिसियां, (v) माल की विशिष्टता के संबंध में प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-4) और (vi)) माल को पहचानने योग्य बनाने के लिए पैकिंग सूचियाँ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एस.टी.सी. को भेजी गईं। एस.टी.सी. इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर इन्हें अपने बैंकरो के माध्यम से मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज, लुधियाना और मेसर्स हरबंस एंड कंपनी लुधियाना को भेज दिया गया। इन दस्तावेजों को संबंधित फर्म द्वारा भुगतान पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। बाद में इन याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में माल जारी करने के लिए सहायक सीमा शुल्क नियंत्रक, बॉम्बे के पास आवश्यक प्रविष्टि बिल दाखिल किए। इस आशय से दोनों पक्षों के तथ्य स्वीकार किये जाते हैं।

(42) नहरीकृत वस्तुओं के आयात लाइसेंस निस्संदेह एस.टी.सी. के नाम पर जारी किए जाते हैं। याचिकाकर्ता फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने तर्क दिया कि चूंकि एस.टी.सी. माल आयात करता है; आदेश की धारा 5 (3) (ii) के अनुसार यह यथावत है। लाइसेंसधारी की संपत्ति, जो उनके अनुसार, आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क द्वारा निकासी तक एस.टी.सी. है, आदेश के खंड 5 (3) (1) और (ii) इस प्रकार है

"ऐसे प्रत्येक लाइसेंस की यह शर्त मानी जाएगी कि-

(1) कोई भी व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी लाइसेंस के लिए ट्रांस द्वारा स्थानांतरण या अधिग्रहण नहीं करेगा, सिवाय उस प्राधिकारी की लिखित अनुमति के तहत जिसने लाइसेंस दिया है या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार:

(ii) वह वस्तु जिसके आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है। आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी:

बशर्ते कि इस उप-खंड के आइटम (i) और (ii) के तहत शर्तें जारी किए गए लाइसेंस के संबंध में लागू नहीं होंगी। भारतीय राज्य व्यापार निगम और केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य समान संस्थानों या एजेंसियों को, जिन्हें सौंपा गया है! आयात के नहरीकरण के साथ।"

ऊपर दी गई लाइसेंसधारी और लाइसेंस की परिभाषा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता के अनुसार, माल का स्वामित्व तब तक रिलीज ऑर्डर धारक में निहित नहीं माना जा सकता जब तक कि माल को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिल जाती। सीमाशुल्क विभाग। आदेश के खंड 8 में लाइसेंसधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति को एसटीसी के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने या माल के आवंटन से वंचित करने का प्रावधान है। या कुछ मामलों में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम और आदेश के खंड 8 ए में एक ही प्रकार के व्यक्तियों के लाइसेंस के निलंबन के प्रावधान हैं। आदेश की उचित सराहना के लिए इन खंडों के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

"8. केंद्र सरकार या आयात और निर्यात का मुख्य नियंत्रक किसी लाइसेंसधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम, या किसी अन्य समान एजेंसी के माध्यम से आयातित वस्तुओं का लाइसेंस या आवंटन प्राप्त करने से रोक सकता है, और इस संबंध में उसके खिलाफ की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्देश दे सकता है कि इस आदेश के तहत उसे किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए आयातित वस्तुओं का कोई लाइसेंस या आवंटन नहीं दिया जाएगा।

* * *

(8-क) केन्द्रीय सरकार या आयातों और निर्यातों का मुख्य नियंत्रक भारतीय राज्य व्यापार निगम, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम, या किसी अन्य समान अभिकरण के माध्यम से किसी अनुज्ञप्तिधारी या आयातक या किसी अन्य व्यक्ति को, खंड 8 में उल्लिखित एक या अधिक आरोपों में विनिधान लंबित रहने तक, इस निमित्त उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयातित वस्तुओं के अनुज्ञप्ति या आवंटन को निलंबित कर सकता है। "

आदेश के दोनों खंडों से पता चलता है कि माल को एसटीसी के माध्यम से आयात किया जाना है।

(43) माल का आयात परिशिष्ट 34 के अनुसार जारी आदेश के आधार पर किया जाना है, जो उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया है, जिसने निर्यात किए गए माल के आधार पर इसके लिए पात्रता अर्जित की है। तर्क दिया गया है कि एस.टी.सी. गैर-निर्यातक होने के कारण वह माल आयात करने का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने रिलीज ऑर्डर, अनुलग्नक पी-38 और पी-39 की प्रतियों का हवाला दिया, जो पहले के अवसरों पर जारी किए गए मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज, लुधियाना के नाम पर हैं। उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया है- "एस.टी.सी. के आयातित स्टॉक से निम्नलिखित वस्तुओं को बाहर निकालने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।" इन अनुलग्नों में दिखाई दे रहा है। रिहाई आदेश के रूप में, जैसा कि आदेश के परिशिष्ट 34 में दिया गया है, ये शब्द नहीं मिलेंगे। चूंकि एस.टी.सी. माल का आयात नहीं करता है, वह स्वामी के रूप में इनका आयात नहीं कर सकता है। नियमों में दी गई "लाइसेंस" की परिभाषा संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि "वह व्यक्ति जिसे आदेश के तहत

लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट दिया गया है।" याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता के तर्क का सार यह है कि लाइसेंस एस.टी.सी. के नाम पर जारी किया जाता है। यह "लाइसेंसधारी" की परिभाषा के दायरे में आता है। एस.टी.सी. के उप विपणन प्रबंधक श्री पी. आर. साहनी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत अपने अतिरिक्त हलफनामे में। उन्होंने कहा कि निर्यातकों ने अपनी आयात पात्रता के विरुद्ध माल आयात करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास आवेदन दायर किया था। आवेदन पर विचार के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने उनके पक्ष में सीधे लाइसेंस जारी करने के स्थान पर रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया। यह आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तिका नियम और प्रक्रिया के अनुच्छेद 97(3)(सी) द्वारा समर्थित है, जिसका प्रभाव है -

"लाइसेंसिंग प्राधिकरण लागू आयात नीति के संदर्भ में योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करेगा। कैनालाइज्ड मदों के संबंध में, आवेदक को सीधा लाइसेंस जारी करने के बजाय, लाइसेंसिंग प्राधिकरण परिशिष्ट 34 में दिखाई देने वाले प्रोफार्मा में, कैनालाइज्ड एजेंसी पर आवेदक के पक्ष में रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। "

परिशिष्ट 34

(अध्याय IV का पैरा 97) रिहाई आदेश का प्रपत्र

आवेदक के लिए मूल

एसटीसी/एमएमटीसी के लिए डुप्लिकेट, प्रायोजन प्राधिकारी के लिए तीन प्रतियाँ

कार्यालय रिकॉर्ड के लिए चार प्रतियाँ

आवंटिती की श्रेणी

आरईपी (व्यापारी-निर्यातक) आरईपी (एक्सपोर्ट-हाउस)

एयू (एसएसआई) एयू (डीजीटीडी)

ए यू (गैर-एसएसआई-गैर-डीजीटी) प्राथमिकता/गैर-प्राथमिकता आईडीएजे/गैर-आईडीए

आखरी उत्पाद। निर्यात/गैर-निर्यात

. इकाइयाँ।

ए यू (कम प्राथमिकता)

ए यू (उच्च प्राथमिकता) एयू (गैर-निर्यात);

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय

रिलीज ऑर्डर क्रमांक..... 73

का कार्यालय

को _____

v_

विषय:-एमएमटीसी/एसटीसी सज्जनों के माध्यम से..... का आवंटन। मैं

आपके आवेदन/पत्र, दिनांक..... के संदर्भ में। उपरोक्त विषय पर, मैं यह कहने के लिए लिखता हूँ कि आप नीचे उल्लिखित वस्तुओं का आवंटन प्राप्त करने के लिए एस.टी.सी./एमएमटीसी से संपर्क कर सकते हैं: -

क्रम संख्या माल का विवरण मात्रा। यदि कोई हो तो सीमित करें
सी.आई.एफ. मूल्य आंकड़े शब्द.

2. यह रिलीज ऑर्डर मूल रूप में एस.टी.सी./एम.टी.एम.सी..... को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- मेसर्स (आवंटी का नाम और पता)
- 3
- 5.

भवदीय,
आयात और निर्यात नियंत्रक
सील के लिए"

(44) इस रिलीज ऑर्डर के माध्यम से आवेदक को एस.टी.सी. के माध्यम से आवंटन किया जाता है। सरकार की आयात नीति के कारण। रिहाई आदेश की एक प्रति एस.टी.सी. को भेजी जाती है। कौन सा लाइसेंस प्राधिकारी से थोक के लिए लाइसेंस प्राप्त करता है। एस.टी.सी. फिर खरीद बैठकों में माल का चयन करने के बाद इन लाइसेंसों के विरुद्ध रिलीज ऑर्डर धारकों के आयात कोटा को समायोजित करें।

(45) बहस के दौरान दो आयात लाइसेंस प्रस्तुत किए गए, एक नंबर पी/ए/1315117 सीके 30 डी27/28/3 पी, दिनांक 29 मार्च, 1969, रुपये के अनुमानित मूल्य के माल के आयात के लिए। 42759 और दूसरा क्रमांक K/2621173/q/xx/39/D/31-32, दिनांक 28 जून 1971, अनुमानित मूल्य रु. केवल 6016151। यदि ये लाइसेंस एस.टी.सी. टी.सी. को जारी नहीं किए गए थे, तो उसे भेजे गए रिलीज आदेश के आधार पर राशियाँ इतनी नहीं हो सकती थीं।

(46) नियम दो प्रकार के लाइसेंस पर विचार करते हैं; एक उन वस्तुओं के लिए है जो नहरीकृत नहीं हैं और दूसरा उन वस्तुओं के लिए है जो नहरीकृत नहीं हैं। पूर्व के मामले में आयात लाइसेंस सीधे आवेदकों के नाम पर जारी किए जाते हैं और बाद के मामले में, आयात व्यापार नियंत्रण नियमों और प्रक्रिया के पैराग्राफ 97(3)(सी) में निहित आयात नीति के कारण जारी किए जाते हैं। यह कैनालाइजिंग एजेंसी के नाम पर जारी किया जाता है, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के नियम 5(3) (आईएल) के प्रावधान में एस.टी.सी. को शामिल नहीं किया गया है। ऑपरेशन से. 1955 के नियम 5(3)(ii) के नियम। इसी प्रकार आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के नियम 8 और 8-ए, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, एक अंतर बनाते हैं। एक लाइसेंसधारी और एस.टी.सी. के बीच "के माध्यम से" शब्द डालने से एस.टी.सी. यदि एस.टी.सी. उस समय शब्द के सामान्य अर्थ में इसे लाइसेंसधारी के रूप में समझा जाता था। इन दोनों में "राज्य व्यापार निगम" के माध्यम से शब्द। नियम अतिशयोक्तिपूर्ण होंगे। यही कारण है कि एस.टी.सी. इंडेंट आदि में प्रतिनिधित्व कर रहा था, कि वह रिलीज ऑर्डर धारकों की ओर से कार्य कर रहा था। प्रोफार्मा में निहित है परिशिष्ट 34 में, जब नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों के प्रकाश में देखा जाता है तो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि लाइसेंसधारी वास्तव में रिलीज ऑर्डर धारक हैं और एसटीसी को यह नाम केवल आयात व्यापार नियंत्रण आदेशों के कानून के उल्लंघन के कारण दिया गया है। याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता का तर्क, कि एस.टी.सी. लाइसेंसधारी होने के कारण माल का मालिक है, का कोई महत्व नहीं है।

(47) अगला प्रश्न जो उठता है और पक्षकारों के वकील द्वारा उठाया गया है, वह यह है कि क्या एस.टी.सी. मालिक के रूप में माल का आयात नहीं किया है तो उसने किस हैसियत से काम किया। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह के अनुसार, इसने याचिकाकर्ता-फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य किया, जो

रिलीज ऑर्डर धारक हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम (1872) की धारा 182 "एजेंट" और "प्रिंसिपल" को निम्नानुसार परिभाषित करती है: -

"एजेंट" वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति के लिए ऐसा कार्य किया जाता है, या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसे 'प्रिंसिपल' कहा जाता है।"

12 वें संस्करण में एजेंसी पर अपनी पुस्तक में। बोस्टेड एजेंसी को इस प्रकार परिभाषित करता है:-

"एजेंसी वह रिश्ता है जो दो व्यक्तियों के बीच मौजूद होता है, जिनमें से एक, प्रमुख, स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से सहमति देता है कि दूसरा, एजेंट, उसी तरह सहमति देते हुए, उसे फिर से प्रस्तुत करना चाहिए या उसकी ओर से कार्य करना चाहिए।"

एजेंसी व्यक्त भी हो सकती है और निहित भी। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, तीसरा संस्करण, खंड 1 (पृष्ठ 152) में एजेंसी के निर्माण का वर्णन इस प्रकार किया गया है: -

"एजेंसी का अनुबंध प्रिंसिपल और एजेंट के व्यक्त या निहित समझौते द्वारा या उसकी ओर से किए गए एजेंट के कार्यों के प्रिंसिपल द्वारा अनुसमर्थन द्वारा बनाया जाता है,

निहित एजेंसी पार्टियों के आचरण या स्थिति या आवश्यकता से उत्पन्न होती है।"

एस्टोपेल द्वारा भी एजेंसी बनाई जा सकती है। हैल्सबरी ने उसी पुस्तक (पृष्ठ 158) में इस प्रकार दर्ज किया है:

"रोक द्वारा एजेंसी तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जिससे दूसरे को यह विश्वास हो कि उसने किसी तीसरे व्यक्ति को उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया है, और यह कि इस तरह के विश्वास में अन्य व्यक्ति ऐसे प्रत्यक्ष प्राधिकरण के दायरे में तीसरे व्यक्ति के साथ लेनदेन में प्रवेश करता है। इस मामले में प्रथम उल्लिखित व्यक्ति को निरोध के सामान्य कानून के तहत तीसरे व्यक्ति की एजेंसी के तथ्य को नकारने से रोक दिया जाता है, और यह मायने नहीं रखता है कि क्या प्रत्यक्ष एजेंट के पास वास्तव में कोई अधिकार नहीं था, या केवल अपने वास्तविक अधिकार से अधिक काम किया था।"

(48) मौजूदा मामले में, अनुलग्नकों के रूप में रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि एस.टी.सी याचिकाकर्ता-फर्मों की ओर से कार्य कर रहा था। ऊनी वस्तुओं के निर्यातक होने के कारण याचिकाकर्ता-फर्मों को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उनकी आयात पात्रता के आधार पर रिलीज ऑर्डर मिले। खरीद बैठकों में माल के चयन के बाद, उन्होंने एस.टी.सी. पर खरीद मांगें रखीं। आयात के लिए उनकी ओर से सामग्री की खरीद के लिए। इंडेंट में एस.टी.सी. याचिकाकर्ता-फर्मों के कारण खरीदार के रूप में दिखाया गया है। कवरिंग लेटर में, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-3 है, -जिसके माध्यम से मांगपत्र मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज, लुधियाना को भेजा गया था, यह उल्लेख किया गया था कि सामान उसकी ओर से खरीदा गया था और वह उतार-चढ़ाव और भिन्नता के लिए जिम्मेदार होगा। विनिमय की दर. दस्तावेजों की प्रतियां विदेशी विक्रेताओं द्वारा सीधे मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज को भेजी गईं। एस.टी.सी. द्वारा दावा किया गया लाभ का कोई मार्जिन नहीं है। और इसे सेवा शुल्क के रूप में केवल 2.25 प्रतिशत मिलता है। शिपिंग दस्तावेज एस.टी.सी. द्वारा भेजे गए थे। याचिकाकर्ता-फर्मों को जो उनके द्वारा सेवानिवृत्त हुए थे। मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज के चालान और माल ढुलाई पत्रों में क्रेता के रूप में उल्लेख किया गया है। आदेश का खंड 5

(3) (ii) दस्तावेजों को रिटायर करने के बाद एस.टी.सी. पर लागू नहीं होता है। ये थे सी.आई.एफ. ठेके। जब इन सभी कारकों पर संयुक्त रूप से विचार किया गया तो एक और केवल एक ही निष्कर्ष निकला कि एस.टी.सी. ने याचिकाकर्ता-फर्मों के रिलीज ऑर्डर धारकों के एजेंट के रूप में कार्य किया और उन्होंने इसकी स्थिति को इस रूप में स्वीकार किया। यह एजेंसी कानून के कार्यान्वयन, पार्टियों की स्थिति और रोक के द्वारा बनाई गई थी। याचिकाकर्ता-फर्मों को अब इस स्थिति को चुनौती देने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता-फर्मों रिलीज ऑर्डर धारक के रूप में जो कुछ भी कर सकती थीं, उन्होंने माल का चयन करने और एस.टी.सी. से पूछने में किया। अपनी एजेंसी के माध्यम से आयात करना। एस.टी.सी. इस प्रकार रिलीज ऑर्डर धारक और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक नाली पाइप था। इसने इन दोनों व्यक्तियों को एक सौदे पर बातचीत करने के लिए एक साथ लाया था जो सामान की खरीद के लिए एक अनुबंध में परिणत हुआ। यह मूलधन के रूप में माल का आयात नहीं करता था।

(49) कलकत्ता उच्च न्यायालय के गंभीरमुल महिबीरप्रसाद बनाम इंडियन बैंक लिमिटेड और एक अन्य मामले के निर्णय में, वादी ने कलकत्ता स्थित बैंक से कहा था, जिसकी शाखा रंगून में थी और उसके पास माल को कलकत्ता को फिर से भेजने या बीमित कराने के लिए शिपिंग दस्तावेज थे। बैंक प्रतिवादी नं. 1, प्रतिवादी नं. 2, जो उसके पक्ष में जमा किए जाने की स्थिति में माल को कलकत्ता भेजने के लिए सहमत हुए। प्रतिवादी-बैंक ने डिफेंडेंट नं. 2 और अपने एजेंट को फिर से शिपमेंट के लिए निर्देश जारी किए। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बैंक के माध्यम से, जो वादी के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच अनुबंध की गोपनीयता स्थापित की गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 री-शिपिंग की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक एजेंट था।

इस निर्णय का सिद्धांत मौजूदा मामले पर लागू होता है और मुझे ऊपर उल्लिखित अन्य परिस्थितियों के साथ एक निष्कर्ष वापस करने में मदद करता है कि एस.टी.सी. ने माल का आयात केवल याचिकाकर्ता-फर्मों के एजेंट के रूप में किया था, मूलधन के रूप में नहीं। बीच के रिश्ते। याचिकाकर्ता-फर्मों और एस.टी.सी. यह प्रिंसिपल और एजेंट का था, न कि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का।

(50) याचिकाकर्ता-फर्मों की ओर से यह भी विवादित है कि माल का स्वामित्व उनके पास नहीं गया है। खरीद में। उन्होंने सी.एल.एफ. के लिए मांग की थी। अनुबंध और पार्टियों के पास था। इसके लिए सहमत हो गये। मेसर्स राज स्पिननिंग मिल्स बनाम मेसारा ए और जी किंग लिमिटेड रागियन मिल्स, इंग्लैंड (14) में पंजाब उच्च न्यायालय की डिबीजन बेंच के फैसले में, जॉनसन बनाम टेलर ब्रदर्स एंड कंपनी में लॉर्ड एटकिंसन द्वारा निर्धारित सिद्धांत। लिमिटेड (15), भरे गए थे, जिनमें लिखा था-

"इस नियम के अनुसार विक्रेता अपने अनुबंध से बंधा हुआ है

छह काम करो. सबसे पहले, माल का चालान बनाना

बिका हुआ। दूसरा, अनुबंध में निहित विवरण के शिपमेंट माल को बंदरगाह पर भेजना। तीसरा, माल ढुलाई का एक अनुबंध प्राप्त करना जिसके तहत माल होगा। अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य पर वितरित किया गया। चौथा, व्यापार में मौजूदा शर्तों पर बीमा की व्यवस्था करना, जो खरीदार के लाभ के लिए उपलब्ध होगा। पांचवां, सभी उचित प्रेषण के साथ वार्ड और निविदा के लिए खरीदार को इन शिपिंग दस्तावेजों को भेजने के लिए, अर्थात्, चालान, लदान का बिल और खरीदार को आश्वासन वितरण की नीति, खरीदे गए सामान की डिलीवरी का प्रतीक है, इसे यहां रखना खरीदार का जोखिम और विक्रेता को उनकी कीमत का भुगतान करने का अधिकार देना।"

विदेशी विक्रेताओं ने इन सभी शर्तों का अनुपालन किया और अपने हिस्से के दायित्वों का पालन किया और दस्तावेज़ एस.टी.सी. को भेज दिए। याचिकाकर्ता-फर्मों को आवक प्रसारण के लिए। एस.टी.सी ने बदले में इन दस्तावेजों को याचिकाकर्ता-फर्मों को उनके बैंकों के माध्यम से भेज दिया। 1972 के मांगपत्र संख्या 7014 और 618 के मामले में दस्तावेजों को सेवानिवृत्त करके याचिकाकर्ता-फर्मों ने अनुबंध के दायित्वों के अपने हिस्से का निर्वहन किया। इंग्लैंड में 1882 में ही यह मान्यता थी कि माल का मालिकाना हक क्रेता को लदान के बिल और मालिकाना हक के अन्य दस्तावेजों के हस्तांतरण पर दिया गया था, जब माल अभी भी खुले समुद्र में था। सैंडर्स ब्रदर्स बनाम मैकलीन एंड कंपनी में रिपोर्टर का यह सिद्धांत इस प्रकार है:-

"वाहक के हाथों में रहते हुए समुद्र में एक कार्गो अनिवार्य रूप से भौतिक वितरण में असमर्थ है। पारगमन और यात्रा की इस अवधि के दौरान, कानूनी व्यापारी द्वारा लदाई के बिल को सार्वभौमिक रूप से इसके प्रतीक के रूप में मान्यता दी जाती है, और लदाई के बिल की खरीद और डिलीवरी कार्गो की एक समान डिलीवरी के रूप में काम करती है। माल में संपत्ति इस तरह के समर्थन और लदान के बिल की डिलीवरी से गुजरती है, जब भी पक्षों का इरादा होता है कि संपत्ति को गुजरना चाहिए, ठीक उसी तरह की परिस्थितियों में संपत्ति माल की वास्तविक डिलीवरी से गुजरती है। और माल में ऐसी संपत्ति को पारित करने और उसके पूर्ण अधिकार के लिए अनुसमर्थक के अधिकार को पूरा करने के उद्देश्य से, माल का बिल, जब तक कि माल की पूरी डिलीवरी तट पर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं की जाती है जो इसके तहत सही दावा करता है, एक प्रतीक के रूप में लागू रहता है, और इसके साथ न केवल माल का पूर्ण स्वामित्व होता है, बल्कि शिपर और शिप मालिक के बीच परिवहन के अनुबंध द्वारा बनाए गए सभी अधिकार भी होते हैं। यह एक चाबी है जो एक सही मालिक के हाथ में है, जिसका उद्देश्य गोदाम के दरवाजे को खोलना है, तैरता हुआ या स्थिर, जिसमें माल होने की संभावना हो सकती है। "

(51) ई. क्लेमेंस होस्ट कंपनी बनाम बिडेल ब्रदर्स में यह अभिनिर्धारित किया गया था: -

"लेकिन जहाज पर सामान की डिलीवरी कब होती है? यह तट पर माल की डिलीवरी से काफी अलग बात हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि जब माल समुद्र में होता है तो माल के बिल की डिलीवरी को माल की डिलीवरी के रूप में माना जा सकता है, यह कानून इतना पुराना है कि मुझे लगता है कि इसके लिए प्राधिकरण को संदर्भित करना काफी अनावश्यक है। "

(52) अर्नहोल्ड कारबर्ग एंड कंपनी बनाम ब्लाइट, ग्रीन जॉर्डन एंड कंपनी में, यह आयोजित किया गया था: -

"यह सच है कि इस मामले में विचाराधीन अनुबंध में सामान को आम तौर पर कीमत तय करने के लिए पहुंचना चाहिए, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से जहाज को छोड़ दिए गए रूप में पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि, यदि वे लदाई की तारीख के बिल के बाद तीन महीने की समाप्ति तक नहीं पहुंचे हैं, तो उचित दस्तावेजों की निविदा के खिलाफ कीमत देय है, क्या माल कभी आएगा या नहीं। "

(53) मैनब्रे सैकरिन कंपनी लिमिटेड बनाम कॉर्न प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड में, माल ले जाने वाला जहाज डूब गया था और विक्रेताओं को इसके नुकसान की जानकारी थी। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया: -

"मैं मानता हूँ कि सामान की बिक्री के लिए एक सामान्य अनुबंध की तुलना में एक साधारण सी.आई.एफ. अनुबंध की आवश्यक विशेषता इस तथ्य में निहित है कि सौदे का प्रदर्शन दस्तावेजों की डिलीवरी से पूरा किया जाना है, न कि माल की वास्तविक भौतिक डिलीवरी से। विक्रेता। खरीदार केवल पारंपरिक दस्तावेजों की डिलीवरी की मांग कर सकता है। यह खरीदार के अधिकार की माप और विक्रेता के कर्तव्य की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। खरीदार दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं कर सकता है और वास्तविक सामान की मांग नहीं कर सकता है, न ही विक्रेता दस्तावेजों को रोक सकता है और जिस सामान का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसे टेंडर कर सकता है। स्कूटन एल.जे., 8 वें संस्करण, पृष्ठ द्वारा चार्टर-पार्टियों पर ग्रंथ में स्थिति को वजन और स्पष्टता के साथ बताया गया है। 167, अनुच्छेद 59 के नोट्स में इस प्रकार है: 'सीआईएफ बिक्री पर सभी प्रश्नों पर विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यह महसूस करना है कि माल की बिक्री का यह रूप माल का प्रतिनिधित्व करने वाले दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा किया जाना है, यह ऐसे दस्तावेज हैं जो माल की डिलीवरी करवाने का अधिकार देते हैं या यदि वे खो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो जहाज के मालिक या हामीदारों से उनका मूल्य वसूलने का संभावित अधिकार देते हैं। इसका परिणाम यह है कि माल की बिक्री अधिनियम, 1893 में विभिन्न नियम, जो मुख्य रूप से भूमि पर माल की बिक्री और वितरण के संबंध में तैयार किए गए हैं, केवल सी.आई.एफ. पर लागू किए जा सकते हैं। बिक्री यथोचित परिवर्तन सहित। और ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें खरीदार को दस्तावेजों की डिलीवरी के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, हालांकि वह उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, और हालांकि किसी भी समझदार अर्थ में माल में कोई संपत्ति भी उसके पास नहीं जा सकती है, यानी, यदि माल लदान के बिल को छोड़कर किसी जोखिम से खो गया है, और पॉलिसी द्वारा बीमाकृत नहीं किए गए जोखिम से, लदान का बिल और पॉलिसी अभी भी अनुबंध द्वारा अपेक्षित उचित वाणिज्यिक रूप में है।"

मेसरा राज स्पनिंग मिल्स केस (सुप्रा) में अंग्रेजी मामलों के सिद्धांतों का पालन किया गया था। जे. वी. गोकल एंड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम सहायक कलेक्टर बिक्री-कर (निरीक्षण) और अन्य, आदि (20) में, सैंडर्स ब्रदर्स मामले (सुप्रा) के बाद, यह देखा गया: -

"व्यावसायिक दुनिया में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लदान का बिल माल का प्रतिनिधित्व करता है और इसका हस्तांतरण माल के हस्तांतरण के रूप में संचालित होता है।"

(54) सी.आई.पी. पर कानून. इंग्लैंड में भी अनुबंध अच्छी तरह से तय हो गया है। जैसा कि भारत में और इन अनुबंधों के मामले में, जब भी प्रथागत दस्तावेज, यानी, लदान का बिल, आदि तैयार किए जाते हैं और खरीदारों को वितरित किए जाते हैं, तो माल में संपत्ति उनके पास चली जाती है। सैंडर्स ब्रदर्स के मामले (सुप्रा) में बोवेन, एल.जे. की भाषा का उपयोग करें, "यह एक चाबी है जो एक असली मालिक के हाथ में है जिसका उद्देश्य गोदाम के दरवाजे को खोलना है, चाहे वह तैर रहा हो या स्थिर हो, जिसमें सामान गिर सकता है होना।" 1972 के इंडेंट नंबर 7014 और 618 में याचिकाकर्ता-फ़रमा ने दस्तावेजों को सेवानिवृत्त कर दिया। उस सेवानिवृत्ति के बाद वे बिल में प्रवेश कर गये। सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के साथ प्रविष्टि, जो आदेश के 10-ए के खंड 10-ए के अनुसार माल की रिहाई के लिए मालिक द्वारा दर्ज की जानी है। याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता का तर्क, कि याचिकाकर्ता-फर्म एस.टी.सी. के एजेंट के रूप में कार्य कर रही थीं। आधार पर प्रवेश बिल दर्ज करने में। इसके द्वारा उनके पक्ष में जारी किया गया प्राधिकरण सी.आई.एफ. के तहत खरीदार के शीर्षक के साथ असंगत है। प्रथागत दस्तावेजों की समाप्ति के बाद अनुबंध। यहां तक कि बीमा पॉलिसी, जो दस्तावेजों का एक हिस्सा थी, मेसर्स लांब्रा इंडस्ट्रीज, लुधियाना के पक्ष में रिक्त रूप से पृष्ठांकित की गई थी। उन्होंने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्ति को पूरा करने के लिए माल को विकृत करने के लिए उत्परिवर्तकों को भी नामांकित किया, उनका आचरण माल में स्वामित्व के निहितार्थ के अनुरूप था और उन्होंने माल के मालिक के

अधिकारों के प्रति असंगत या अपमानजनक कोई कार्य नहीं किया। चीजें। सीमा शुल्क के बाद प्रवेश बिल, याचिकाकर्ता-फर्मों के पास बहुत लंबे समय तक रहा। वे अब यह नहीं कह सकते कि माल में स्वामित्व पारित नहीं हुआ है। उन्हें। यदि सी.एल.एफ. की शर्तों का कोई उल्लंघन होता है। अनुबंध, जिसका उन्होंने रिट याचिकाओं में उल्लेख नहीं किया है, जिसका माल पर कोई असर नहीं है। उस स्थिति में तथ्य का विवादित प्रश्न होने के कारण इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, इन दोनों इंडेंटों के माल का स्वामित्व याचिकाकर्ता-फर्मों में सर्वोत्तम है।

(55) मांगपत्र क्रमांक 625/72 की स्थिति भिन्न नहीं है। उस मामले में मेसर्स हरबंस एंड कंपनी ने दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे वापस नहीं लिया। सी.आई.एफ. अनुबंध में, यह कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करता है। जैसे ही विक्रेता उस दायित्व का निर्वहन करता है, जो उससे अपेक्षित है और माल भेजता है और दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है, तो माल में स्वामित्व क्रेता को दे दिया गया माना जाता है। यह ऊपर उल्लिखित मामलों का अनुपात है। रुस्तमजी ए दुबाश बनाम हाजी हुसैन लारी और अन्य में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक मामले में, समान परिस्थितियों में यह कहा गया था: -

“लेकिन हालाँकि जहाँ तक सी.आई.एफ. का संबंध है। खरीदार और संपत्ति का आयात करने वाले व्यक्ति के बीच अनुबंध तब पारित होगा जब माल भेजा जाएगा।”

इंडेंट नंबर 625/72 (कॉपी अनुलग्नक पी-3) के संबंध में पत्र से पता चलता है कि खरीद एस.टी.सी. द्वारा की गई थी। मेसर्स के कारण; हरबंस एंड कंपनी, लुधियाना। यदि याचिकाकर्ता-फर्म को एस.टी.सी. के साथ पिछले लेनदेन का अच्छा अनुभव नहीं है। या अपने अधिकारियों के आचरण के कारण असुविधा या हानि का सामना करना पड़ा, तो बिलों और अन्य दस्तावेजों को अस्वीकार करना उचित उपाय नहीं था। एस.टी.सी. में विश्वास के कथित उल्लंघन से फर्म को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं। या यहां तक कि अनुबंध, सामान्य नागरिक कानून के तहत इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

(56) एस.टी.सी. इसकी तुलना पक्की आढतियों से नहीं की जा सकती क्योंकि आढतियों की विशेषताएं एस.टी.सी. की कार्यप्रणाली में नहीं पाई जाती हैं।

दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता-फर्मों को माल को अस्वीकार करने का अधिकार है क्योंकि ये विनिर्देशों के अनुसार नहीं थे, यानी ये चिथड़े नहीं थे। जैसा कि कस्टम अधिकारियों ने कहा है। 1972 के इंडेंट नंबर 7014 और 618 में, उन्होंने दस्तावेजों को रिटायर करने और प्रवेश बिलों में प्रवेश करने के लंबे समय के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों की आपत्तियों को पूरा करने के लिए, आपत्तियों को संतुष्ट करने के लिए माल को विकृत करने की पेशकश की। अब उन्हें पलट कर यह कहने में बहुत देर हो चुकी थी कि उन्होंने माल अस्वीकार कर दिया है या अस्वीकार करना चाहते हैं। सीआईएफ अनुबंध में अस्वीकृति का अधिकार भी उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग जल्द से जल्द संभव अवसर पर किया जाना चाहिए। किसी भी रिट याचिका में ऐसी अस्वीकृति के बारे में कोई दलील नहीं दी गई थी और इसे एस.टी.सी. द्वारा अपनाए गए रुख से उत्पन्न स्थिति की तात्कालिकताओं को पूरा करने के लिए बहस के दौरान उठाया गया था।

दूसरी ओर रिट याचिकाओं को पढ़ने से याचिकाकर्ता-फर्मों की अब भी सामान प्राप्त करने की उत्सुकता का पता चलता है। इंडेंट नंबर 625 में दस्तावेजों को अनुबंध के अनुरूप न होने की दलील पर नहीं, बल्कि एसटीसी के साथ उनके व्यवहार में मेसर्स हरबंस एंड कंपनी के दुखद अनुभव के आधार पर सम्मानित

करने से इनकार कर दिया गया था। उनके पिछले अनुबंध में, यानी 1972 के इंडेंट नंबर 618 में। क्या ये भविष्य के सामान थे, निश्चित या अज्ञात सामान थे या वितरण योग्य स्थिति में थे, ये सभी तथ्य के प्रश्न हैं जिन पर इस रिट याचिका में विचार नहीं किया जा सकता है जैसा कि होना चाहिए सबूतों से साबित हुआ। सवाल यह है कि खारिज करने का अधिकार याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है या नहीं? यदि हां, तो कब और किन परिस्थितियों में, यह फिर से कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में रखा गया है। सामान की अस्वीकृति से क्षति के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न होगा, जो फिर से नागरिक न्यायालयों के लिए निर्णय लेने का मामला है।

(57) सिविल रिट याचिका संख्या 4709/1975 में, चूंकि माल का स्वामित्व याचिकाकर्ता फर्म को एस.टी.सी. को दे दिया गया था। याचिकाकर्ता-फर्म को माल पुनः वितरित नहीं किया जा सकता जहां तक सीमा शुल्क अधिकारियों का संबंध है, याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा माल को विकृत करने के लिए म्यूटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए उन्हें दिया गया वचन पूरा नहीं किया गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों की नजर में मेसर्स ओसवाल स्पिनिंग मिल्स अपने परिसर में जगह की कमी के कारण काम नहीं कर सका। उसके बाद याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। आर.पी. भट्ट, जे. द्वारा मेसर्स नागेश होजरी मिल्स बनाम एम.आर.रामचंद्रन और अन्य (22) मामले में बंबई उच्च न्यायालय का एक असूचित निर्णय इस आशय का है कि जिस सामान को विक्रेताओं द्वारा विधिवत कटा हुआ प्रमाणित किया गया था, अनुपयोगी और न पहनने योग्य चीथड़े हैं। याचिकाकर्ता-फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रेषण के देश में प्रचलित लत्ता के विवरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सीमा शुल्क अधिकारी माल को रोक नहीं सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता-कंपनियों ने खुद ही कटे-फटे टुकड़ों को हटाने का बीड़ा उठाया था। रिट याचिका संख्या 4709/1975 में हमारे सामने रखी गई सामग्री पर, माल की रिहाई के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

(58) बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अपने नियमों के अनुसार, माल को तब तक अपने पास रखता है, जब तक कि उसे असली मालिक द्वारा वहां से हटा नहीं दिया जाता। यदि निकासी में देरी होती है तो माल के मालिक को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिसे विलंब शुल्क के रूप में जाना जाता है। मेसर्स लांबा इंडस कोशिशें उन छूटों को माफ करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही थीं, लेकिन पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों द्वारा बार-बार मांग करने के बावजूद वह मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रही। पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों ने यह स्थिति अपनाई कि यदि दस्तावेज उसे सौंपे जाते हैं तो वह सहानुभूतिपूर्वक आपत्ति निवारण के मामले पर विचार करेगा। बहस के दौरान एस.टी.सी. के विद्वान वकील ने मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज को विलंब शुल्क माफ कराने के लिए अपना पूरा समर्थन देने का भी आश्वासन दिया। किसी भी स्थिति में विलंब शुल्क का भुगतान माल के मालिक को करना होगा।

(59) मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज की दूसरी प्रार्थना यह है कि वह इंडेंट संख्या 701-7/1972 के माल के कब्जे का हकदार है, जिसे मेसर्स कैमल निटिंग एंड टेक्सटाइल मिल्स, लुधियाना, प्रतिवादी संख्या की खरीद मांग पर आयात किया गया था। 7. इसने एस.टी.सी. के सुझाव पर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैसे का भुगतान किया था। प्रतिवादी नंबर 7 का कहना है कि अगर सामान उसे पहुंचा दिया जाए तो वह पैसे देने को तैयार है। मेसर्स लांबा इंडस्ट्रीज, लुधियाना ने क्यों और किन परिस्थितियों में पैसे का भुगतान किया था, यह फिर से तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, जब तक कि मेसर्स कैमल निटिंग एंड टेक्सटाइल मिल्स नहीं। लुधियाना, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति से, माल हस्तांतरित करता है, या लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर मेसर्स लांबा इंडस को इंडेंट नंबर 7015/1972 के खिलाफ आयातित

माल आवंटित करता है, इसे इसके लिए हकदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह मामला फिर से अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(60) सिविल रिट याचिका क्रमांक 238/1975 में एस.टी.सी. सूचित किया कि यदि उसने इंडेंट संख्या 625/1972 के विरुद्ध माल का भुगतान नहीं किया तो वह भविष्य में याचिकाकर्ता के रिलीज ऑर्डर की तामील नहीं करेगा। याचिकाकर्ता फर्मों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाई गुप्ता के अनुसार, यह वास्तव में रिलीज ऑर्डर को अस्वीकार करने जैसा है क्योंकि वह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आयात के अपने अधिकार के विरुद्ध आयात नहीं कर सकते हैं। उनके अनुसार, एस.टी.सी. ही एकमात्र एजेंसी है जिसके माध्यम से वह रिहाई आदेश को अमल में ला सकते हैं। आदेश के खंड 8, 8-ए और 8-बी ही एकमात्र प्रावधान हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी भी नहरीकृत वस्तु को आयात करने से रोका जा सकता है या उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है या उसकी आयात पात्रता को स्थगित किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, इन खंडों के तहत शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं, और एसटीसी को अपने आयात अधिकार के लिए काम करने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता-कंपनियों के विद्वान वकील श्री जवाहर लाल गुप्ता के तर्क में पहली नजर में कुछ दम नजर आता है। एस.टी.सी. रिलीज ऑर्डर धारक द्वारा चयनित सामग्री की खरीद आवश्यकता के अनुपालन में खरीदारी करता है और विदेशी विक्रेता को भुगतान करता है। यह विदेशी विक्रेता को भुगतान से बच नहीं सकता क्योंकि उसे विदेशी बैंक में उसके पक्ष में एक अपरिवर्तनीय साख पत्र खोलना होगा। प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया है कि एस.टी.सी. इंडेंट संख्या 625/1972 के मामले में, रिलीज ऑर्डर धारकों के दिमाग की अनियमितताओं पर पैसे का भुगतान छोड़कर इसके द्वारा भुगतान किए गए पैसे को अवरुद्ध करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। यदि कई मामलों में ऐसा हुआ है तो विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने का उद्देश्य ही एस.टी.सी. के माध्यम से आयात को बढ़ावा देना है। जो किया गया था उसके असफल होने की संभावना है क्योंकि विदेशी मुद्रा ऐसे ही सौदेबाजी में बंधी रहेगी। एस.टी.सी. के अधिकारियों की अपेक्षा की कमी के कारण यह स्थिति निर्मित हुई। रिलीज ऑर्डर धारक, यानी मेसर्स हरबंस एंड कंपनी से एस.टी.सी. के पक्ष में अपरिवर्तनीय साख पत्र स्थापित करने के लिए जोर न देना। एस.टी.सी. की स्थिति चाहे जो भी हो। ऐसे मामलों में अपने पैसे को रोकने के वित्तीय फायदे या नुकसान के बारे में वह केंद्र सरकार द्वारा रिलीज ऑर्डर के रूप में जारी किए गए आदेशों को नकार नहीं सकता है। याचिकाकर्ता-फर्म को सेवा देने से इनकार करके रिहाई के आदेशों को विफल करने के लिए उसे ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था। फिर कठिनाई यह होगी कि एस.टी.सी. कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी होना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है और एसटीसी के इनकार से उत्पन्न होने वाली याचिकाकर्ता-फर्म की कठिनाई और कठिनाई। इसकी ओर से आयात करने का समाधान नहीं किया जा सकता। मेसर्स हरबंस एंड कंपनी के पास भी सी.आई.एफ. के तहत दस्तावेजों का सम्मान करने से इनकार करने के कारण इसके पक्ष में इक्विटी नहीं है। इंडेंट संख्या 625/1972 का अनुबंध और यह न्यायालय दोनों इंडेंट के माल को अपने पक्ष में जारी करने का आदेश नहीं दे सकता। इस चर्चा के मद्देनजर सिविल रिट याचिका संख्या 238/1975 में याचिकाकर्ता-फर्म की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।

(61) फैसला देने से पहले, मैं एसटीसी के प्रबंधन के विचार के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। याचिकाकर्ता-फर्मों द्वारा अनुलग्नक के रूप में इन रिट याचिकाओं के साथ संलग्न विशाल पत्राचार से पता चलता है कि एसटीसी के उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित अधिकारियों का रवैया कमोबेश असहयोगी था और उन्होंने याचिकाकर्ता-फर्मों को कठिनाइयों से बाहर निकालने में ज्यादा मदद नहीं की। एस. टी. सी. के कुछ प्रयासों से इंडेंट सं. 7014/1972 और 618/1972 को जल्द से जल्द मंजूरी दी जा सकती है और डिमरेज शुल्क के संचय से बचा जा सकता है। एसटीसी को विदेशी मुद्रा के संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने

के लिए लोगों के साथ सहयोग करने के लिए अधिक मानवीय रवैया अपनाना चाहिए, जिसके लिए इसे बनाया गया था। एस. टी. सी. का रवैया इस प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करने में अपने अधिकारियों को श्रेय नहीं देता है। मुझे लगता है कि इसके अधिकारियों के कुछ अभियान और पहल से इस दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमे को बचाया जा सकता था यदि उन्होंने माल की निकासी में संबंधित एजेंसियों के साथ अपने अच्छे कार्यालयों और प्रभाव का उपयोग किया होता। एस. टी. सी. को इन रिट याचिकाओं में कानून की तकनीकीताओं का जो लाभ मिला है, उससे उसके अधिकारियों को अपने घटकों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए।

(62) ऊपर कही गई और चर्चा की गई बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। मामले की प्रकृति को देखते हुए पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आर. एन. मित्तल, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद, हरियाणा